वर्ष : 2 । अंक :1 । सितम्बर 2026 । पृष्ठ : 36 RNI No. UPHIN/25/A0721 मूल्य : 20

हिन्दी मासिक पत्रिका

पॉलिटिकल इमेज



चमत्कार के भरोसे
उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल

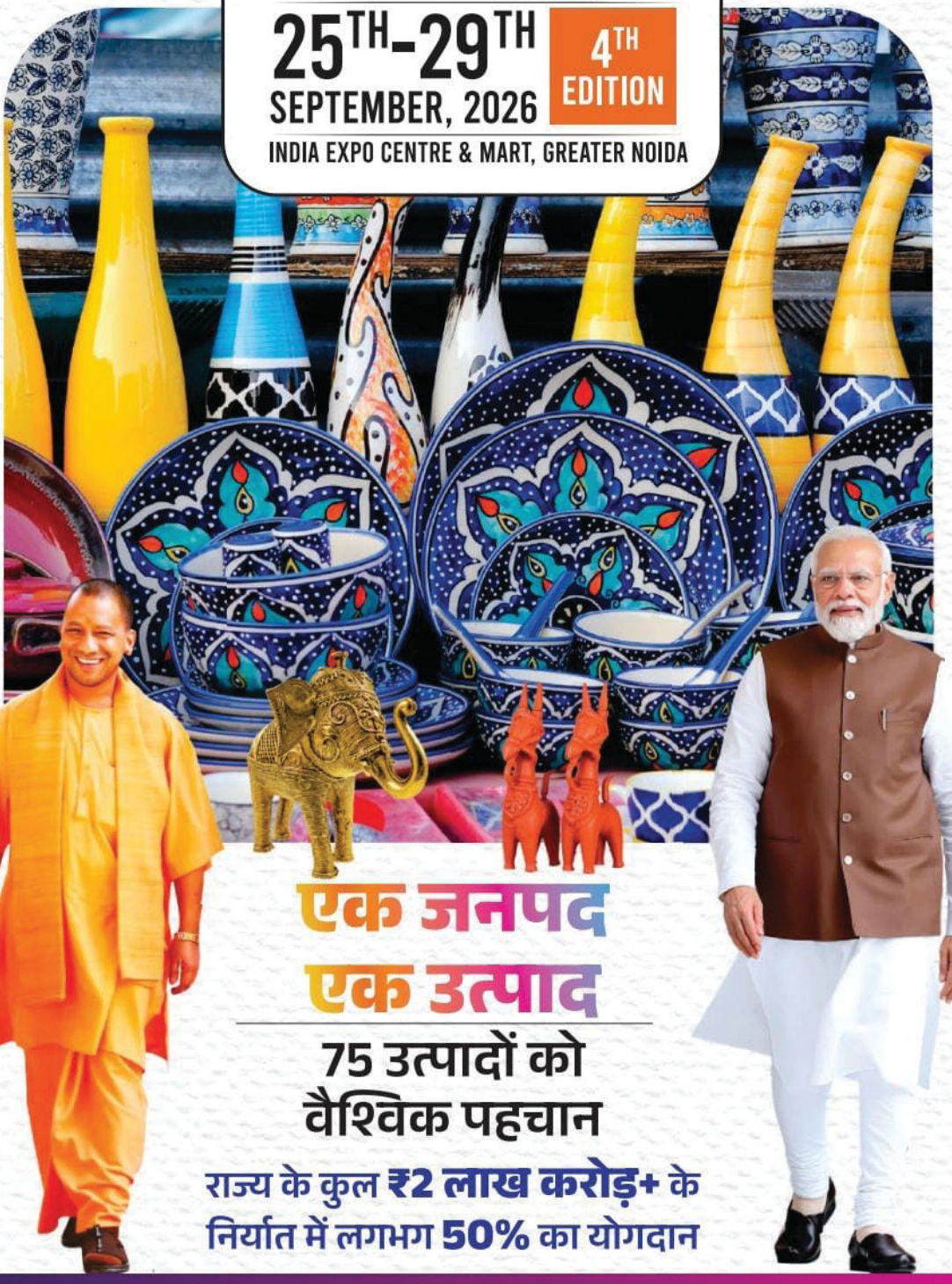
एक जनपद एक उत्पाद
उत्तर प्रदेश

UP INTERNATIONAL TRADE SHOW

25TH-29TH SEPTEMBER, 2026

4TH EDITION

INDIA EXPO CENTRE & MART, GREATER NOIDA



एक जनपद एक उत्पाद

75 उत्पादों को वैश्विक पहचान

राज्य के कुल **₹2 लाख करोड़+** के निर्यात में लगभग **50%** का योगदान

विकास की गति अपार-डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP

पॉलिटिकल इमेज

वर्ष : 2 । अंक : 1 ।
सितम्बर 2026 । पृष्ठ : 36

संपादक
गरिमा सिंह

दिल्ली ब्यूरो चीफ- सिद्धार्थ प्रकाश

राष्ट्रीय ब्यूरो कार्यालय

KH/No **28/2/2** sangam vihar Road No **10**, near kp pharma timarpur

स्वामी, प्रकाशक गरिमा सिंह एवं मुद्रक नीलम श्रीवास्तव द्वारा नीलम प्रिंटिंग प्रेस 41/381 नरही, लखनऊ, ऊ.प्र.-226001 से मुद्रित व सी- 62, इन्दिरा नगर, लखनऊ, ऊ.प्र.-226016 से प्रकाशित।

सम्पादक - गरिमा सिंह

RNI No. UPHIN/25/A0721

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ न्यायालय होगा।

e-mail
singsgarima@gmail.com

Phone : 8595476939



26 **24 साल की उम्र में...**

इस अंक में



चमत्कार के भरोसे उत्तर... 06



04 **उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास...**



'हनुमान अंश' 14

हमारे पिछले अंक


पॉलिटिकल इमेज
कांवड़ यात्रा
आस्था और परंपरा का संगम


पॉलिटिकल इमेज
योगी के सहयोगी
भोजशाला वाग्देवी का मंदिर


पॉलिटिकल इमेज
उत्तर प्रदेश में
व्यापार की
नई तस्वीर


पॉलिटिकल इमेज
UTTAR PRADESH
अनुभव अतुल्य
प्रकृति, पर्यटन
और योगी


पॉलिटिकल इमेज
भारत की पहली
ट्रांसजेंडर पायलट
नैना मेनन


पॉलिटिकल इमेज
पुलिस ट्रेनिंग
बेटियों ने दी मजबूती
अनुशासन, साहस और सेवा की भावना के साथ
नए भारत की बेटियां बन रहीं सुरक्षा की दीवार

संपादक की कलम से...

कांग्रेसी जर्जरता का रहस्य



गरिमा सिंह
सम्पादक

पिछली आठ अक्तूबर ढलने से पूर्व दो राज्यों के चुनावी रुझान स्पष्ट हो चले थे। हमेशा की तरह छोटे परदे पर कई दिग्गज जोरदार बहस-मुबाहिसों में उलझे हुए थे। उसी दौरान एक वरिष्ठ पत्रकार की गौरतलब टिप्पणी थी- जीता हुआ चुनाव हारना कोई कांग्रेस से सीखे और हारा हुआ चुनाव जीतना भाजपा से सीखे। चुनाव-दर-चुनाव कांग्रेस के साथ जो हो रहा है, उस पर आगे चर्चा करेंगे, पहले भाजपा के बारे में बात। वह हारा हुआ चुनाव कैसे जीत लेती है?

जवाब इस किस्से में छिपा है। मतगणना से एक दिन पूर्वमेरे मोबाइल फोन की घंटी बजती है। उधर से, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता बोल रहे थे। उन्होंने पूछा कि आपका हरियाणा के बारे में क्या आकलन है? मैंने प्रतिप्रश्न किया, आप बताइए, आप तो कई दिन हरियाणा में बिताकर आए हैं? उनका उत्तर था,आखिरी कुछ दिनों में वहां की बयार बदली है। हम चुनाव जीतेंगे और सरकार हमारी ही बनेगी। मुझे लगा कि वह अपनी पार्टी की 'पोजिशनिंग' मुझ पर जाहिर कर रहे हैं। हम पत्रकारों के साथ अक्सर ऐसा होता है। अगले दिन जब रुझान साफ हो गया था, उन्होंने दोबारा फोन किया। वह कुछ बोलते, इससे पहले मैंने सवाल दागा- आप कल इतने भरोसे में कैसे थे? जवाब चौंकाने वाला था। वह बोले कि मैं इतना वरिष्ठ हूं, लेकिन मुझे बड़ी जनसभाओं की जगह सिर्फ छोटी पंचायतों में जाने का निर्देश था। ये पंचायतें और गांव, जहां मैं गया, अधिकतर मेरी बिरादरी के लोगों के थे। मैंने कम से कम पांच हजार बुजुर्गों के पैर छुए होंगे। उन सबसे न केवल व्यक्तिगत आशीर्वाद मिला, बल्कि चुनावों में भी लाभ मिला। मैं अकेला नहीं था, मेरे जैसे तमाम नेता इसी काम पर लगाए गए थे। इन सभी को अपने स्वजातियों को 'भटकने' से बचाना था। यहां तक कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे अति वरिष्ठ नेता बड़ी सभाओं की जगह जनसंपर्क और कार्यकर्ता सम्मेलनों पर जोर दे रहे थे। उन्हें हरियाणा का प्रभारी बनाया गया था। उनके साथ जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर जैसे दिग्गजों की जमात थी। इन्होंने विधानसभा क्षेत्रों को आपस में बांट रखा था। उन क्षेत्रों के हर कार्यकर्ता से संपर्क का पूरा प्रयास इन लोगों ने किया, ताकि मतदाताओं के मन से 'एंटी इनकंबेन्सी' का भाव निकालकर उन्हें मतदान केंद्रों तक लाया जा सके। वे इसमें सफल रहे। लोकसभा चुनावों में संघ और कार्यकर्ताओं की बेरुखी भारी पड़ी थी। इस बार उस कमी को दूर किया गया, मत प्रतिशत में तीन प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी इसका प्रमाण है। इसने भगवा दल की जीत में बड़ी भूमिका अदा की। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत गैर-जाट वोटों को जोड़ने में लगा दी। एक तरफ, कांग्रेस 'हुड्डा ऐंड सन' पर जरूरत से ज्यादा निर्भर कर रही थी, तो दूसरी तरफ भाजपा जातिगत गोलबंदी के अलावा लोगों को रह-रहकर याद दिला रही थी कि किस तरह मोदी जी आप लोगों का निजी तौर पर ख्याल रखते हैं। हरियाणा के लिए कौन-कौन सी योजनाओं पर कितना खर्च किया गया और इन योजनाओं से कितने लोग लाभान्वित हुए! इसके साथ पूरे जोर-शोर से हुड्डा काल में गैर-जाटों के साथ हुए कथित भेदभाव को स्थापित करने की कोशिश की गई। आंकड़ों और सामाजिक हकीकत के इस तालमेल ने भाजपा को तीसरी बार सत्ता की चौहद्दियों में दाखिला दिला दिया। यह अपने आप में कीर्तिमान है। यही नहीं, आम चुनाव से ऐन पहले पार्टी ने न केवल नौ साल से अधिक समय से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया, बल्कि अति-पिछडे. नायब सिंह सैनी को तख्तनशीं कर दिया। ऐसे प्रयोग के लिए असाधारण हिम्मत की जरूरत होती है। इसके उलट कांग्रेस वार्धक्य के छोर पर खडे. भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रमुख चेहरा बनने से रोक न सकी। टिकट बंटवारे में कुमारी सैलजा गुट के साथ उभरा विवाद और जनसभाओं से सैलजा की दूरी ने भी वोटरों तक सही संदेश नहीं दिया। आम आदमी पार्टी और उभरते दलित नेता चंद्रशेखर के प्रति बेरुखी भी उसे महंगी पड़ी। ध्यान दें। आप को हरियाणा में 1.79 प्रतिशत मत मिले और कांग्रेस को 39.09 प्रतिशत। यदि कांग्रेस और आप में समझौता हो जाता, तो वे मिलकर भाजपा के 39.94 फीसदी से आगे हो जाते। कांग्रेस आलाकमान ने इसी तरह अपने क्षत्रपों के सामने आत्म-समर्पण कर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ गंवा दिए थे। भाजपा ने इसके उलट अपनी क्षेत्रीय ताकतों वसुंधरा राजे, रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान को किनारे कर दिया था। वे चुनाव नरेंद्र मोदी की शख्सियत पर लड़े और जीते गए थे। कांग्रेस को अपने संगठन का शिराजा बचाने के लिए कुछ राज्यों में परचम फहराने की सख्त जरूरत है, लेकिन लगातार जीतने की कुव्वत वह कब की गंवा चुकी है। आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा से भले ही कोई अच्छी खबर न आई हो, लेकिन जम्मू-कश्मीर ने अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर यकीनन मुस्कान ला दी होगी।



उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए यूनिफाइड मॉडल भवन विनियम-2026 तैयार

प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाला राज्य बनाने के लक्ष्य को और अधिक गति प्रदान करने एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भवन निर्माण और विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा यूनिफाइड मॉडल भवन विनियम-2026 तैयार किया गया है। जिसके तथ्यों का आज पिकप भवन में आयोजित बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी के समक्ष अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया। बैठक में सभी तथ्यों पर विस्तृत चर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये गए।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यीडा, गीडा, यूपीसीडा और यूपीडा के लिए बनाए गए यूनिफाइड मॉडल भवन विनियम से मैन्यूफेक्चरिंग, पर्यटन, आईटी, आईटीईएस, लॉजिस्टिक्स, हेल्थकेयर, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। प्रस्तावित यूनिफाइड मॉडल भवन विनियम-2026 को जल्द ही मंत्री परिषद के समक्ष भेजा जाएगा। जिसकी संस्तुति के बाद भवन निर्माण उपविधि को लागू किया जाएगा।

मंत्री नन्दी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश को गति देने के लिए लगातार नीतिगत सुधार किए जा रहे हैं। यूनिफाइड मॉडल भवन विनियम-2026 इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण सुधार है, जो प्रदेश में विकास को नियंत्रित करने के बजाय विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य करेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस सम्बन्ध में



जो भी विसंगतियां या समस्यायें आ रही हों, उन्हें शासन स्तर से दूर किया जाय।

मंत्री नंदी ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य निवेशकों, उद्यमियों और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए प्रदेश को देश का अग्रणी औद्योगिक एवं आर्थिक केंद्र बनाना है। मॉडल भवन विनियम-2026 प्रदेश में निवेश, रोजगार और आधारभूत संरचना विकास को नई दिशा प्रदान करेंगे।

उन्होंने कहा कि नए विनियम उत्तर प्रदेश को आधुनिक, निवेश-अनुकूल और सतत विकास वाले राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायें। इसके लिए नए भवन विनियमों का उद्देश्य भूमि का अधिकतम और बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, निर्माण प्रक्रिया को सरल बनाना तथा निवेशकों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है। इससे उद्योगों की स्थापना तेज होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।



मंत्री नन्दी ने कहा कि वर्तमान समय की औद्योगिक आवश्यकताओं, बढ़ते निवेश और आधुनिक शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए नए मॉडल भवन विनियम तैयार किए जाने से सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भवन निर्माण नियमों में एकरूपता आएगी और प्रक्रियाएं अधिक सरल एवं पारदर्शी होंगी।

बैठक में बताया गया कि मॉडल भवन विनियम-2026 में भूमि के बेहतर उपयोग और ऊर्ध्वाधर विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। नए नियमों के तहत-भू-आच्छादन, सेटबैक और पार्किंग मानकों को तर्कसंगत बनाया गया है। विभिन्न श्रेणियों में एफएआर में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। सड़क की चैड़ाई के आधार पर अनुमेय एफएआर को बढ़ाया गया है। 45 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर एफएआर की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। इससे सीमित भूमि पर अधिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और शहरों के अनियंत्रित विस्तार को नियंत्रित करते हुए आधुनिक एवं सघन विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

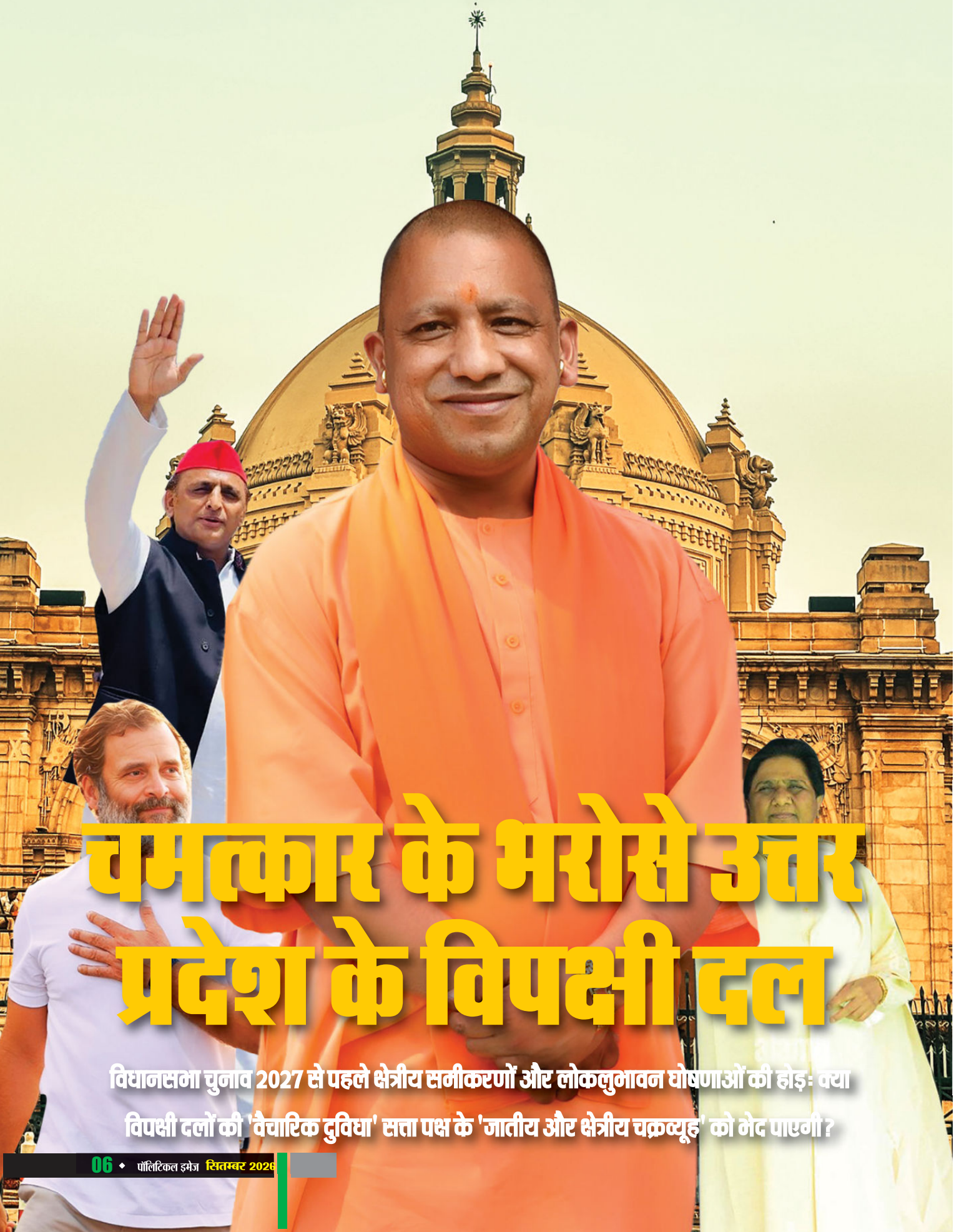
बताया गया कि नए विनियमों में भवन निर्माण की अनुमति प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। प्रमुख प्रावधानों में-100 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखंडों तथा 30 वर्गमीटर तक के वाणिज्यिक भूखंडों के लिए 1 पंजीकरण शुल्क पर पंजीकरण एवं स्व-प्रमाणीकरण की व्यवस्था की गयी है। निर्धारित सीमा तक तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा तैयार नक्शों के आधार पर डीम्ड स्वीकृति का प्रावधान है। डीम्ड एनओसी अप्रूवल सिस्टम विकसित करने की पहल, पुराने भवनों में कंपाउंडिंग, एडिशन एवं ऑल्टरेशन पर भी नए नियम लागू होंगे।

मॉडल भवन विनियमों में औद्योगिक उपयोग के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें फ्लैटेड फैक्टरी, एमएसएमई इकाइयां, गैर-एमएसएमई उद्योग, वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स इकाइयों तथा डाटा सेंटर को शामिल किया गया है। 4 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले औद्योगिक भूखंडों पर श्रमिकों के लिए डॉरमेट्री की सुविधा का प्रावधान किया गया है। डाटा सेंटर के लिए अतिरिक्त एफएआर और पार्किंग मानकों में राहत प्रदान की गई है। औद्योगिक क्षेत्रों में स्टिल्ट एवं पोडियम पार्किंग की अनुमति भी दी गई है।

आवासीय क्षेत्र में ग्रुप हाउसिंग, प्लॉटेड विकास और मल्टी यूनिट आवास के लिए नियमों को सरल बनाया गया है। प्रमुख प्रावधानों में-ग्रुप हाउसिंग के लिए न्यूनतम भूखंड आकार 2000 वर्गमीटर निर्धारित, 300 वर्गमीटर तक के भूखंडों पर मल्टी यूनिट श्रेणी का प्रावधान, 1500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले ग्रुप हाउसिंग भूखंडों पर पोडियम पार्किंग की अनुमति, प्रधानमंत्री आवास योजना-2.0 के किफायती आवास मानकों को शामिल किया गया है।

इस व्यवस्था से वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए-12 मीटर या उससे अधिक चैड़ी सड़कों पर वाणिज्यिक भवनों की अनुमति, 20 कमरों तक के होटलों के लिए न्यूनतम भूखंड आकार की बाध्यता समाप्त, बड़े होटलों के लिए न्यूनतम 500 वर्गमीटर भूखंड निर्धारित, आईटी/आईटीईएस, कार्यालय और सर्विस अपार्टमेंट के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र के लिए भी नियमों को व्यावहारिक बनाया गया है। डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, नर्सिंग होम और अस्पतालों के लिए अलग मानक निर्धारित किए गए हैं। एम्बुलेंस पार्किंग का प्रावधान किया गया है। शैक्षणिक संस्थानों के लिए नर्सरी से विश्वविद्यालय स्तर तक भूखंड आकार को तर्कसंगत बनाया गया है। स्कूल बस पार्किंग और पिक-अप ड्रॉप-ऑफ जोन की व्यवस्था भी की गई है। बताया गया कि मॉडल भवन विनियम-2026 में मिश्रित उपयोग और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को विशेष महत्व दिया गया है। 30 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों के किनारे मिश्रित उपयोग विकास को अनुमति दी जाएगी। इससे आवास, वाणिज्यिक गतिविधियों और सेवाओं का संतुलित विकास होगा तथा आधुनिक शहरों के निर्माण को गति मिलेगी। बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी इन्वेस्ट यूपी विजय किरन आनन्द सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।



चमत्कार के भरोसे उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल

विधानसभा चुनाव 2027 से पहले क्षेत्रीय समीकरणों और लोकलुभावन घोषणाओं की होड़: क्या विपक्षी दलों की 'वैचारिक दुविधा' सत्ता पक्ष के 'जातीय और क्षेत्रीय चक्रव्यूह' को भेद पाएगी?

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीतिक बिसात बिछ चुकी है। चुनाव में अब बमुश्किल 6 महीने का समय शेष है और चुनाव अप्रैल-मई में संभावित हैं। लेकिन सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को मात देने का दावा करने वाले विपक्षी खेमे में ज़मीनी स्तर पर एकजुटता से ज़्यादा तालमेल की कमी और आपसी छद्म युद्ध साफतौर पर नज़र आ रहा है।

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही अंदरूनी खींचतान अब खुलकर बयानों में तब्दील होने लगी है। जहाँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और राष्ट्रीय रणनीतिकार 150 से अधिक सीटों पर दावेदारी ठोक रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता उन्हें सीमित सीटों पर समेटने की वकालत करते हुए राज्य की 350 से अधिक विधानसभा सीटों पर अपनी खुद की तैयारी तेज कर चुके हैं। विपक्ष की तीसरी शक्ति बहुजन समाज पार्टी अपने आंतरिक अंतर्विरोधों और समय से पहले प्रत्याशियों के चयन की अनिश्चितता से जूझ रही है। चुनावी देहरी पर खड़े उत्तर प्रदेश के इस परिदृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि विपक्षी पार्टियां मोदी-योगी युग के बदले हुए राजनैतिक यथार्थ को स्वीकार करने के बजाय किसी अलौकिक चमत्कार की उम्मीद में जी रही हैं।

अतीत का आइना: गठबंधन और जीत का गणित (साक्ष्य और आंकड़े)

पिछले चुनावों के परिणाम यह साफ़ गवाही देते हैं कि उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर सत्ताधारी दल के विजय रथ को रोकना किसी एक दल के बूते की बात नहीं है:

2022 विधानसभा चुनाव (अकेले लड़ने का हश्र):

कांग्रेस: कुल 403 सीटों में से 399 पर चुनाव लड़ा, महज़ 2 सीटें जीतीं और 387 सीटों पर ज़मानत ज़ब्त हो गई (कुल मत प्रतिशत: 2.4%)।

बहुजन समाज पार्टी: सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ा, सिर्फ 1 सीट जीत पाई और 290 सीटों पर ज़मानत ज़ब्त हुई (कुल मत प्रतिशत: 13%)।

समाजवादी पार्टी: 347 सीटों पर लड़कर अकेले 111 सीटें जीतीं। सहयोगियों के साथ यह आंकड़ा 125 तक पहुंचा था (कुल मत प्रतिशत: ₹32%)।

2024 लोकसभा चुनाव (गठबंधन का प्रभाव):

जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विपक्षी गठबंधन के तहत साथ आए, तो पासा पलट गया। समाजवादी पार्टी ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीतकर सत्ता पक्ष को तगड़ा झटका दिया। समाजवादी पार्टी का मत प्रतिशत बढ़कर 34% और कांग्रेस का 9.53% हो गया। वहीं अकेले चुनाव लड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी शून्य पर सिमट गई और उसका मत प्रतिशत घटकर 9.46% रह गया।

2019 लोकसभा चुनाव (सपा-बसपा प्रयोग): जब धुर विरोधी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ मिलकर लड़े थे, तब बहुजन समाज पार्टी को 10 और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थीं।

आंकड़े बताते हैं कि सत्ता पक्ष को हराने का एकमात्र फॉर्मूला मजबूत विपक्षी गठबंधन है, लेकिन 2027 से ठीक पहले अहंकार और महत्वाकांक्षाओं के टकराव के कारण इसकी संभावनाएं बेहद कम नजर आ रही हैं।

वोट बैंक को साधने की होड़: भाजपा की नई घोषणाएं और दांव

अक्टूबर 2026 की हालिया राजनैतिक हलचलों और आगामी चुनावों के मद्देनजर भाजपा ने अपनी 'एंटी-इन्कंबेंसी' (सत्ता विरोधी लहर) को काटने के लिए बेहद आक्रामक रुख अपनाया है:

'सेवा संकल्प' और नई कल्याणकारी घोषणाएं: भाजपा ने राज्यव्यापी 'सेवा संकल्प' अभियान शुरू किया है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली और आसपास के क्षेत्रों के ग्राम प्रहरियों को बड़ी सौगातें दी हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी, किसानों और मछुआरों के लिए सीधी वित्तीय सहायता और युवाओं को लुभाने के लिए नए रोजगार मेलों की घोषणा की गई है ताकि हालिया पुलिस और अन्य भर्ती परीक्षाओं के विवादों से उपजे असंतोष को थामा जा सके।

क्षेत्रीय संतुलन का दांव: हाल ही में घोषित सांगठनिक नियुक्तियों और चुनावी सूचियों में भाजपा ने नए क्षेत्रीय चेहरों को मौका देकर सूक्ष्म जातीय प्रबंधन का उदाहरण पेश किया है। इसमें सवर्णों के साथ-साथ गैर-यादव पिछड़ा वर्ग (कुर्मी, मौर्य, राजभर, सैनी) और गैर-जाटव दलितों को भारी प्रतिनिधित्व दिया गया है।

अयोध्या से खुला चैलेंज: 2027 के चुनाव से पहले अयोध्या फिर से सियासत का केंद्र बन गया है। अयोध्या से चुनाव लड़ने की अखिलेश यादव की पुरानी बयानबाजी पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें सीधे अयोध्या से आकर नामांकन करने की खुली चुनौती दे दी है, जिससे भाजपा अपने 'प्रखर हिंदुत्व' और राष्ट्रवाद के नैरेटिव को फिर से धार दे रही है।

विपक्ष का पलटवार: सपा और कांग्रेस की लुभावनी घोषणाएं



भाजपा के इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए विपक्ष ने भी इस बार बड़े और आक्रामक वादे करने शुरू किए हैं:

सपा का ऐतिहासिक दांव - '75 जिलों के लिए 75 घोषणापत्र': अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव के लिए एक अभूतपूर्व रणनीति की घोषणा की है, जिसके तहत समाजवादी पार्टी हर जिले के लिए अलग घोषणापत्र जारी कर रही है। इसके तहत स्थानीय रोजगार, कृषि संकट और जातियों के स्थानीय समीकरण के हिसाब से विशेष योजनाओं और भत्तों का वादा किया जा रहा है।

कांग्रेस का 'न्याय' पत्र और सरकारी नौकरी का वादा: राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए मासिक आर्थिक सहायता (महालक्ष्मी योजना के तहत), युवाओं के लिए 'पहली नौकरी पक्की' का अधिकार और रिक्त पड़े सरकारी पदों को तत्काल भरने की घोषणाओं के सहारे युवाओं और महिला वोट बैंक को सीधे लुभाने में जुटी है।

पी डी ए रथ यात्रा और 'वंशवाद' की नई पीढ़ी: समाजवादी पार्टी पी डी ए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) रथ यात्रा के जरिए जातिगत जनगणना और जिसकी जितनी संख्या, उतना हिस्सा के आधार पर आरक्षण देने का वादा कर रही है। इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश की राजनीति में पुराने दिग्गज परिवारों

की अगली पीढ़ी (नेता पुत्रों) को विधानसभा पहुंचाने के लिए जमीनी स्तर पर सक्रिय कर दिया गया है, जिसे सपा अपना नया 'लॉन्चिंग पैड' बना रही है।

क्षेत्रीय और जातीय चक्रव्यूहः पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के समीकरण

1. पश्चिमी उत्तर प्रदेशः जाट-किसान राजनीति और जेवर का दांव

पश्चिमी यूपी में राजनीति का पारा बेहद गर्म है। यहाँ जाट और किसान मतदाता (जो कुल आबादी का 12 से 17 प्रतिशत हैं) चुनावी रुख तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।

भाजपा का गठजोड़ः भाजपा ने राष्ट्रीय लोकदल (RLD) के जयंत चौधरी को अपने पाले में रखकर इस क्षेत्र को सुरक्षित करने का प्रयास किया है। हापुड़ और मथुरा की रैलियों में भाजपा-आरएलडी की संभावित ताकत का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सरकार जेवर हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी और पश्चिमी यूपी के विकास मॉडल को अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में भुना रही है।

विपक्ष की घेराबंदीः दूसरी तरफ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गन्ने के भुगतान में देरी, बढ़ती बेरोजगारी और एथेनॉल नीतियों को लेकर किसानों के बीच असंतोष को हवा दे रहे हैं ताकि 2024 की तरह इस क्षेत्र में भी भाजपा को नुकसान पहुंचाया जा सके।

2. पूर्वांचलः राजभर-निषाद फैक्टर और विभाजन की राजनीति

उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल (पूर्वी उत्तर प्रदेश) से होकर गुजरता है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा इस क्षेत्र की 26 में से केवल 10 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 14 सीटों पर कब्जा किया था। इस नुकसान की भरपाई के लिए नए प्रयोग जारी हैंः

निषाद आरक्षण का जिन्नः एनडीए की सहयोगी 'निषाद पार्टी' के प्रमुख संजय निषाद लगातार पारंपरिक रूप से नदी किनारे रहने वाले मछुआरा समुदाय के लिए 'मछुआरा/निषाद आरक्षण' की मांग उठा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपनी खोई साख बचाने और ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए उनकी यह मांग भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है।

उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े करने का राजभर का शिगूफाः कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों—पूर्वांचल, अवध प्रदेश, बुंदेलखंड और पश्चिम प्रदेश (हरित प्रदेश)—में विभाजित करने की पुरानी मांग को दोबारा हवा दे दी है। यह बयान सीधे तौर पर पूर्वांचल के मतदाताओं की क्षेत्रीय अस्मिता को उकसाकर विपक्ष के वोट बैंक को बिखेरने की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

अल्पसंख्यक मतदाताः उम्मीदों का बिखराव और नया मोड़

उत्तर प्रदेश में करीब 19 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है, जो पारंपरिक रूप से गैर-भाजपा दलों की रीढ़ रही है। लेकिन अब यह मतदाता आधार पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैः

एआईएम आई एम का प्रवेशः असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी (AIMIM) भले ही खुद चुनाव न जीते, लेकिन वह मुस्लिम बहुल सीटों पर मतों का ध्रुवीकरण कर विपक्ष का खेल बिगाड़ देती है। हाल ही में ओवैसी द्वारा मुख्यमंत्री को संभल से और अखिलेश यादव को गोरखपुर से चुनाव लड़ने का खुला चैलेंज देना इसी आक्रामक राजनीति का हिस्सा है।

पसमांदा कार्डः सत्ता पक्ष लगातार पसमांदा (ग़रीब और पिछड़े) मुसलमानों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देकर अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, जिससे विपक्ष का 'एकमुश्त मुस्लिम वोट' का दावा कमजोर हुआ है।

प्रति-ध्रुवीकरणः अल्पसंख्यक मतों के एकतरफा झुकाव का मुकाबला करने के लिए बहुसंख्यक मतों को एकजुट करने का मंत्र सत्ता पक्ष बखूबी जानता है।



विपक्ष के आंतरिक अंतर्विरोध और कमजोरियां

समाजवादी पार्टी (मुस्लिम-यादव समीकरण की सीमा): यह समीकरण अब अकेले चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त नहीं है। अति-पिछड़ी जातियों की अपनी छोटी पार्टियां सत्ता पक्ष के साथ दृढ़ता से खड़ी हैं, जो



समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।

कांग्रेस (अतीत का दंभ और नेतृत्व संकट): जमीनी स्तर पर संगठन बेहद कमजोर है। हालिया संगठनात्मक फेरबदल में भी पार्टी ने जमीनी चेहरों को तरजीह देने के बजाय आंतरिक संतुलन साधने की कोशिश की, जिससे पिछड़ों-दलितों को नेतृत्व देने का राहुल गांधी का राष्ट्रीय दावा राज्य स्तर पर कमजोर पड़ जाता है।

बहुजन समाज पार्टी (दिल्ली से दौलताबाद का तुगलकी दौर): मायावती भयानक दुविधा में हैं। उनके भतीजे आकाश आनंद को सुबह पार्टी से बाहर किया जाता है और शाम को फिर से राष्ट्रीय संयोजक बना दिया जाता है। इस अनिश्चितता ने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच भारी भ्रम पैदा कर दिया है।

बिना कार्ययोजना के जीती जाएगी जंग?

चुनाव में महज़ कुछ महीने शेष हैं और पूरा विपक्ष इस समय ज़मीनी स्तर पर बूथ प्रबंधन मजबूत करने के बजाय मुख्य चुनाव आयुक्त से जंग, मतों की चोरी के आरोपों और अघोषित आपातकाल के बयानों में उलझा हुआ है। अखिलेश यादव की दुविधा 'कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के बिना' पर टिक गई है, तो कांग्रेस अपनी खोई हुई ज़मीन तलाशने के लिए सहयोगियों पर दबाव बनाने में व्यस्त है। दोनों ही खेमे मुफ्त बिजली, पेंशन, भत्तों और क्षेत्रीय घोषणापत्रों की झड़ी लगा रहे हैं, लेकिन यदि विपक्षी दलों ने अपने व्यक्तिगत दंभ को छोड़कर 2024 की तरह एक ठोस, व्यावहारिक सीट-बंटवारा फॉर्मूला और संयुक्त कार्ययोजना तैयार नहीं की, तो 2027 में 'चमत्कार' की उम्मीद सिर्फ एक राजनीतिक दिवास्वप्न बनकर रह जाएगी, और सत्ता पक्ष आसानी से अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखेगा।

7.8% GDP ग्रोथः पीएम मोदी का विजन और MSME सेक्टर की जमीनी हकीकत

इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 7.8% रही, जो पिछले साल की पहली तिमाही में दर्ज 6.9% से ज्यादा है। हालांकि, यह इस साल जनवरी-मार्च तिमाही में दर्ज वृद्धि दर 8.6% से कम है। ये आंकड़े इसी हफ्ते सोमवार को सरकार ने जारी किए थे। कहा जा रहा है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज़ सेक्टर की अहम भूमिका रही। पहली तिमाही में वृद्धि दर ब्लूमबर्ग के सर्वे में 7.3% के औसत अनुमान और भारतीय रिज़र्व बैंक के 7% के पूर्वानुमान से भी ज़्यादा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वृद्धि को बहुत बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि तेल की कीमतों में झटके, सप्लाई चेन में बाधाएं और वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत ने यह प्रदर्शन किया है। भारत ऑटोमोबाइल और मोबाइल फोन से लेकर फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स और स्टील तक सब कुछ बनाता है और अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भी बड़े पैमाने पर



विकसित करने की कोशिश कर रहा है। मगर, अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 17% है, जो पीएम मोदी के 25% के लक्ष्य से अब भी कम है।

इस ऐतिहासिक आंकड़े पर देश को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा:

यह 7.8% की GDP वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित मजबूती, गतिशीलता और हमारे देश के लोगों के सामर्थ्य को दर्शाती है। हमारी सरकार का ध्यान देश के युवाओं के लिए अधिक से अधिक अवसर पैदा करने, व्यापार को आसान बनाने (Ease of Doing Business) और MSME क्षेत्र को सशक्त बनाकर 'विकसित भारत' की नींव को मजबूत करने पर है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



धरातल पर सुधार और एमएसएमई की उम्मीदें



एक तरफ जहां सरकारी आंकड़े और नीतियां अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ होने का संकेत दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के रीढ़ माने जाने वाले एमएसएमई (MSME) क्षेत्र के प्रतिनिधि इस विकास को जमीनी धरातल पर अधिक प्रभावी बनाने की वकालत कर रहे हैं। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) के सचिव ज्योति प्रकाश जायसवाल का मानना है कि आंकड़ों की यह बढ़त तभी संभव है, जब इसका असर स्थानीय स्तर पर भी मैन्युफैक्चरिंग एवं डिमांड पर दिखेगा। देश की आर्थिक विकास दर 7.8% होना एक अच्छी खबर है। साथ ही हमारा मानना है कि स्थानीय स्तर पर भी मैन्युफैक्चरिंग और डिमांड में बढ़ोतरी होने से इन आंकड़ों को और सबल मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 'स्वदेशी' और 'आत्मनिर्भरता' के आह्वान का भी स्वागत है, क्योंकि इससे स्थानीय स्तर पर 'वोकल फॉर लोकल' को बढ़ावा मिलेगा और देश की MSME इकाइयों को बड़े ऑर्डर मिलने से विकास दर बढ़ने के साथ रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

-ज्योति प्रकाश जयसवाल, सचिव, आईआईए

चुनौतियों का समाधान: कच्चे माल, जीएसटी और बैंकिंग सुधार

उद्योग जगत के अनुसार, विकास दर की रफ्तार को बनाए रखने के लिए एमएसएमई सेक्टर की मुख्य परिचालन बाधाओं को दूर करना बेहद जरूरी है। वर्तमान में कच्चे माल की अनिश्चित कीमतें और लॉजिस्टिक्स की ऊंची लागत छोटे और मध्यम उद्यमियों के मार्जिन को प्रभावित कर रही हैं।

प्रमुख मांगे और सुझाव

लागत नियंत्रण व जीएसटी राहत: उद्यमियों का कहना है कि कच्चे माल और लॉजिस्टिक्स लागत पर से जीएसटी दरों को तार्किक बनाकर या राहत देकर विनिर्माण (Manufacturing) को गति दी जा सकती है।

सस्ता और सुलभ ऋण: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि वे एमएसएमई इकाइयों को बिना किसी जटिल प्रक्रिया के समय पर ऋण उपलब्ध कराएं।

ब्याज दरों में कटौती: लोन की ब्याज दरों में राहत मिलने से उद्यमी अपनी वर्किंग कैपिटल बढ़ा सकेंगे और अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार कर सकेंगे।

'वोकल फॉर लोकल' से 'विकसित भारत' का रास्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'आत्मनिर्भर भारत' और 'वोकल फॉर लोकल' का विज़न देश के एमएसएमई सेक्टर को वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनाने का खाका तैयार करता है। यदि केंद्र सरकार और आरबीआई स्तर पर उद्योगों की व्यावहारिक समस्याओं जैसे- कच्चे माल की लागत, बैंकिंग प्रक्रिया और कर दरों में राहत पर त्वरित कदम उठाए जाते हैं, तो 7.8% की यह जीडीपी ग्रोथ न केवल स्थिर रहेगी, बल्कि बड़े पैमाने पर नए रोजगार के अवसरों का सृजन भी करेगी।

आस्था से अर्थव्यवस्था तक

उत्तर प्रदेश पर्यटन ने लिखी विकास की नई कहानी

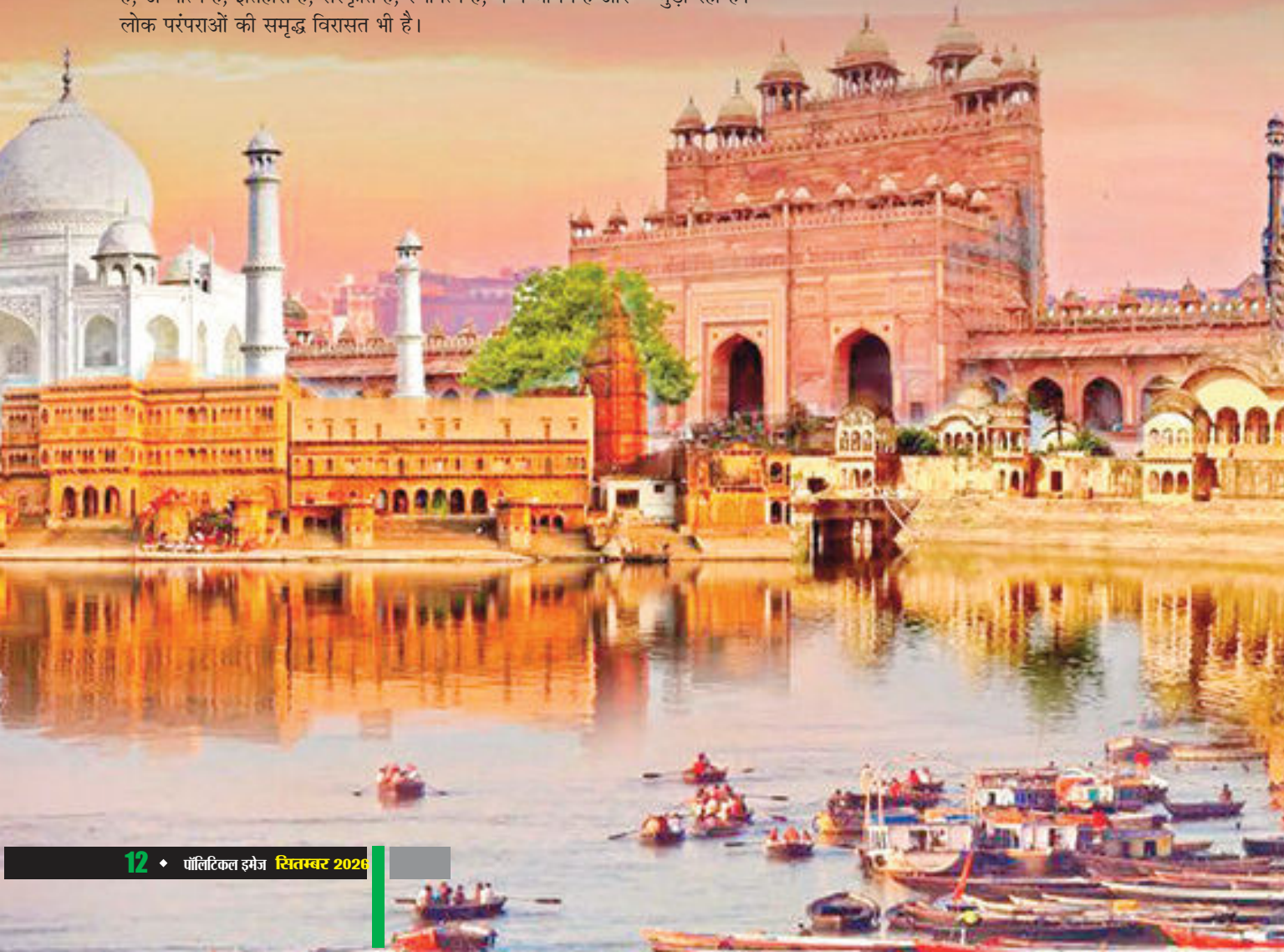
योगी सरकार में आध्यात्मिक विरासत से वैश्विक पहचान तक-अयोध्या, काशी मथुरा से लेकर बौद्ध सर्किट और वन्य पर्यटन तक बदल रही प्रदेश की तस्वीर

भारत की सांस्कृतिक आत्मा यदि किसी प्रदेश में सबसे अधिक सजीव दिखाई देती है, तो वह उत्तर प्रदेश है। भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या, भगवान श्रीकृष्ण की लीलाभूमि मथुरा-वृंदावन, भगवान शिव की अनादि नगरी काशी, भगवान बुद्ध की ज्ञान और उपदेश परंपरा से जुड़ी सारनाथ और कुशीनगर की भूमि, जैन तीर्थों की गौरवशाली विरासत और विश्वविख्यात ताजमहल—ये सभी उत्तर प्रदेश को विश्व पर्यटन मानचित्र पर एक विशिष्ट स्थान प्रदान करते हैं।

उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता है। यहां धर्म है, अध्यात्म है, इतिहास है, संस्कृति है, स्थापत्य है, वन्य जीवन है और लोक परंपराओं की समृद्ध विरासत भी है।

हालांकि लंबे समय तक इतनी विशाल पर्यटन संभावनाओं के बावजूद प्रदेश का पर्यटन क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाया था। पिछले कुछ वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पर्यटन को केवल धार्मिक यात्रा तक सीमित रखने के बजाय इसे विकास, रोजगार, सांस्कृतिक संरक्षण और वैश्विक पहचान से जोड़ने की दिशा में प्रयास किया है।

योगी सरकार के दौर में पर्यटन को एक समग्र आर्थिक गतिविधि के रूप में देखने की सोच मजबूत हुई है। धार्मिक पर्यटन के साथ हेरिटेज, आध्यात्मिक, इको-टूरिज्म, ग्रामीण और सांस्कृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर उन शहरों में दिखाई देता है, जिनकी पहचान सदियों से आस्था और संस्कृति से जुड़ी रही है।



अयोध्या से काशी तक—आस्था के केंद्रों का कायाकल्प

अगर उत्तर प्रदेश के पर्यटन विकास में सबसे बड़े बदलाव की बात की जाए तो अयोध्या सबसे प्रमुख उदाहरण के रूप में सामने आती है।

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के साथ अयोध्या में बड़े पैमाने पर आधारभूत सुविधाओं का विकास हुआ है। सड़कें, रेलवे स्टेशन, हवाई संपर्क, घाट, पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था और पर्यटकों के लिए सुविधाओं के विस्तार ने अयोध्या को एक बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का आधार तैयार किया है। अयोध्या में बढ़ती पर्यटक और श्रद्धालु गतिविधियों का असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देता है। होटल, रेस्तरां, परिवहन, फूल-माला, प्रसाद, हस्तशिल्प और स्थानीय कारोबार से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं।

काशी में भी विकास और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। काशी विश्वनाथ धाम परियोजना ने मंदिर परिसर को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा है। गंगा घाटों का संरक्षण, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और देव दीपावली जैसे आयोजनों ने वाराणसी की पर्यटन पहचान को और मजबूत किया है। आज काशी केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है। वह भारतीय संस्कृति, दर्शन, संगीत, अध्यात्म और सनातन परंपरा का वैश्विक प्रतीक बनकर उभर रही है। इसी प्रकार मथुरा-वृंदावन और बरसाना में ब्रज संस्कृति को पर्यटन से जोड़ने की दिशा में काम हुआ है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि, बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, गोवर्धन परिक्रमा और बरसाना जैसे धार्मिक स्थलों के आसपास सुविधाओं के विकास से श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यात्रा अधिक सुगम बनाने का प्रयास किया गया है।

ब्रज की होली, जन्माष्टमी और अन्य सांस्कृतिक आयोजनों को बड़े स्तर पर प्रस्तुत किए जाने से ब्रज की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार मिला है।

बुद्ध की धरती से दुनिया तक

उत्तर प्रदेश की पर्यटन विरासत केवल हिंदू धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं है। प्रदेश बौद्ध धर्म की विश्वव्यापी विरासत का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। सारनाथ वह पवित्र भूमि है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया। वहीं कुशीनगर भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण से जुड़ा प्रमुख स्थल है। श्रावस्ती, संकिसा और कौशांबी भी बौद्ध परंपरा में विशेष महत्व रखते हैं। योगी सरकार ने बौद्ध सर्किट के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया है। इन स्थलों पर सड़क, पर्यटन सुविधाओं और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन से अंतरराष्ट्रीय बौद्ध पर्यटकों के लिए उत्तर प्रदेश की यात्रा को नई सुविधा मिली है। दक्षिण-पूर्व एशिया और अन्य देशों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बौद्ध सर्किट को जोड़ने की संभावनाएं बढ़ी हैं। यह पर्यटन की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक कूटनीति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारत की बौद्ध विरासत को दुनिया के उन देशों से जोड़ने में उत्तर प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, जहां बौद्ध धर्म की बड़ी आबादी और गहरी सांस्कृतिक जड़ें हैं। इसके अलावा चित्रकूट, विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटन की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। इन क्षेत्रों का संतुलित विकास स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है।





‘हनुमान अंश’

के बाद क्यों उमड़ा नीम करौली बाबा के कैंची धाम में जनसैलाब?

एक संत की जीवन-यात्रा, हनुमान भक्ति का संदेश और सिनेमा का प्रभाव—फिल्म की लोकप्रियता ने कैंची धाम को फिर सुर्खियों में ला दिया। लेकिन नीम करौली बाबा कौन थे और उनकी शिक्षाओं में ऐसा क्या है, जो दशकों बाद भी लोगों को आकर्षित करता है।

एक ओर उत्तराखंड की पहाड़ियों में स्थित एक आध्यात्मिक आश्रम, दूसरी ओर बड़े सितारों और भारी बजट वाली फिल्मों के बीच अपनी जगह बनाती एक फिल्म। इन दोनों के बीच की कड़ी हैं नीम करौली बाबा—एक ऐसे संत, जिनका नाम भारत के साथ-साथ विदेशों में भी श्रद्धा के साथ लिया जाता है।

फिल्म ‘हनुमान अंश’ की लोकप्रियता ने इन दिनों बाबा के जीवन और उनकी आध्यात्मिक विरासत को नए सिरे से चर्चा में ला दिया है। फिल्म की कहानी, कम बजट में बड़े बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की खबरें और उत्तराखंड के कैंची धाम में उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़ ने एक साथ कई सवाल खड़े किए हैं।

क्या किसी फिल्म के जरिए एक संत की शिक्षाएं नई पीढ़ी तक पहुंच सकती हैं? क्या पर्दे पर दिखाई गई आध्यात्मिक कहानी लोगों को वास्तविक धार्मिक स्थलों की ओर आकर्षित करती है? और जब आस्था के केंद्र पर श्रद्धालुओं की संख्या अचानक बढ़ जाती है, तो उसके साथ कौन-सी चुनौतियां पैदा होती हैं?

‘हनुमान अंश’ की कहानी इन सवालों को समझने का एक अवसर देती है।

‘हनुमान अंश’: छोटे बजट से बड़ी व्यावसायिक चर्चा तक

फिल्म ‘हनुमान अंश’ का निर्देशन डॉ. विशाल चतुर्वेदी ने किया है। फिल्म नीम करौली बाबा के जीवन से प्रेरित आध्यात्मिक कहानी प्रस्तुत करती है। फिल्म की आधिकारिक वेबसाइट इसे बाबा के जीवन से प्रेरित सिनेमाई यात्रा बताती है, न कि संपूर्ण जीवनी या ऐतिहासिक दस्तावेज। फिल्म 7 अगस्त 2026 को देशभर में रिलीज हुई थी।

फिल्म की शुरुआती चर्चा का प्रमुख कारण इसका बताया गया कम बजट था। समाचारों में इसकी लागत दो करोड़ रुपये से कम बताई गई, जबकि शुरुआती बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट में इसकी कमाई 272.23 करोड़ रुपये तक पहुंचने का उल्लेख हुआ था।

लेकिन 11 अक्टूबर 2026 तक तस्वीर और आगे बढ़ चुकी थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया* की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने अपने 65वें दिन तक दुनिया भर में 431.85 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन दर्ज किया था। यह आंकड़ा समाचार रिपोर्ट में प्रकाशित दावा है; इसे निर्माता के वास्तविक मुनाफे के बराबर नहीं समझना चाहिए।

फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले शोभिनव सत्या सहित कलाकारों की प्रस्तुति, आध्यात्मिक कथानक और पारिवारिक दर्शकों तक पहुंचने की इसकी क्षमता भी चर्चा में रही। दर्शकों के एक वर्ग को फिल्म की साफ-सुथरी भाषा और पारिवारिक प्रस्तुति पसंद आने की बात कही गई।

हालांकि, फिल्म की सफलता को केवल धार्मिक आस्था से जोड़ देना पर्याप्त नहीं होगा। इसकी कहानी, प्रदर्शन, प्रचार, दर्शकों की प्रतिक्रियाएं और सिनेमाघरों में उपलब्धता जैसे पहलुओं का भी योगदान हो सकता है।

फिल्म की आधिकारिक वेबसाइट भी इसे केवल ऐतिहासिक घटनाओं का पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि भक्ति और सेवा की भावना को केंद्र में रखकर बनाई गई सिनेमाई यात्रा बताती है।

नीम करौली बाबा कौन थे?

नीम करौली बाबा को नीब करौरी बाबा और महाराज-जी के नाम से भी जाना जाता है। उनके जीवन से जुड़ी जानकारी के अनुसार, उनका मूल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा बताया जाता है। वे भगवान हनुमान के अनन्य भक्त थे और उनके अनुयायी उन्हें प्रेम, सेवा, करुणा तथा भक्ति का प्रतीक मानते हैं।

बाबा का जीवन किसी बड़े राजनीतिक पद, धन-संपत्ति या सार्वजनिक सत्ता के इर्द-गिर्द नहीं, बल्कि साधना, सादगी और आध्यात्मिक प्रभाव के कारण याद किया जाता है। उनसे जुड़े अनेक प्रसंगों में जरूरतमंदों की सहायता, लोगों को भोजन कराना और जीवन में प्रेम का महत्व समझाना प्रमुख हैं।

11 सितंबर 1973 को वृंदावन में उन्होंने देह त्यागी। इसके बावजूद उनसे जुड़ी आध्यात्मिक परंपरा और उनके अनुयायियों की आस्था आगे बढ़ती रही।

उनकी लोकप्रियता का एक महत्वपूर्ण पक्ष विदेशों में उनके विचारों का प्रसार भी है। राम दास, जिनका पूर्व नाम रिचर्ड अल्पर्ट था, जैसे पश्चिमी अनुयायियों के लेखन और संस्मरणों ने बाबा के बारे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिज्ञासा बढ़ाने में भूमिका निभाई।

यहां एक तथ्यात्मक अंतर समझना आवश्यक है। बाबा के अनुयायी उनसे जुड़ी कई घटनाओं को चमत्कार के रूप में देखते हैं, लेकिन उन सभी घटनाओं की स्वतंत्र ऐतिहासिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इसलिए उनके जीवन पर लिखते समय प्रमाणित जीवन-विवरण, अनुयायियों के अनुभव और धार्मिक मान्यताओं को अलग-अलग पहचानना जरूरी है।

कैंची धाम: पहाड़ियों में बसा वह आश्रम, जिसकी पहचान दुनिया तक पहुंची

उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भवाली और अल्मोड़ा की ओर जाने वाले मार्ग के पास स्थित कैंची धाम नीम करौली बाबा से जुड़ा प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र है।

आश्रम की स्थापना से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथि 15 जून 1964 मानी जाती है, जब यहां हनुमान मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा हुई थी। समय के साथ यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए आस्था, प्रार्थना और सामुदायिक सेवा का केंद्र बन गया।

कैंची धाम का महत्व केवल मंदिर के दर्शन तक सीमित नहीं है। यहां आयोजित होने वाला वार्षिक भंडारा, आश्रम का शांत वातावरण और बाबा से जुड़ी शिक्षाएं इसे विशिष्ट पहचान देते हैं।

यहां पहुंचने वाले कई श्रद्धालु बाबा के जीवन से जुड़े प्रसंगों को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं और कुछ समय आध्यात्मिक वातावरण में बिताते हैं। कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के बीच मानसिक शांति की तलाश में भी ऐसे स्थलों पर जाते हैं। हालांकि, प्रत्येक श्रद्धालु का अनुभव अलग हो सकता है।

कैंची धाम की प्रसिद्धि यह भी दिखाती है कि किसी धार्मिक स्थल की पहचान केवल उसके निर्माण या इतिहास से नहीं बनती। उससे जुड़ी परंपराएं, लोगों की स्मृतियां, सामुदायिक आयोजन और पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताएं भी उसकी पहचान का हिस्सा होती हैं।

बाबा की चार प्रमुख शिक्षाएं: प्रेम, सेवा, भोजन और ईश्वर-स्मरण

नीम करौली बाबा की शिक्षाओं का सार अक्सर चार विचारों में व्यक्त किया जाता है—सबसे प्रेम करना, सबकी सेवा करना, सबको भोजन कराना और ईश्वर का स्मरण करना।

उनसे जुड़ी आध्यात्मिक परंपरा में इन विचारों का अंग्रेजी रूप भी प्रचलित है: ₹Love everyone, serve everyone, feed everyone,





remember God₹ इन्हें बाबा की शिक्षाओं के सार के रूप में समझना उचित है; किसी विशिष्ट हिंदी वाक्य को उनका प्रमाणित शब्दशः उद्धरण मानने के लिए अलग स्रोत आवश्यक होगा।

प्रेम करो:किसी व्यक्ति का सम्मान उसकी जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति या सामाजिक पहचान के आधार पर कम नहीं होना चाहिए।

सेवा करोः जरूरतमंद की सहायता, बीमार की देखभाल और दुखी व्यक्ति की बात सुनना भी सेवा के रूप हैं।

भोजन कराओः भूखे व्यक्ति को भोजन उपलब्ध कराना केवल धार्मिक पुण्य का विषय नहीं, बल्कि मानवीय जिम्मेदारी भी है।

ईश्वर का स्मरण करो:भक्ति को विनम्रता, आत्मचिंतन और अच्छे कर्मों से जोड़ना इन शिक्षाओं का व्यापक भाव है।

इन विचारों की विशेषता यह है कि इन्हें समझने के लिए किसी बड़े धार्मिक आयोजन की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में भी इन मूल्यों को अपनाने का प्रयास कर सकता है।

फिल्म के बाद कैंची धाम में क्यों बढ़ी भीड़?

'हनुमान अंश' की लोकप्रियता के साथ कैंची धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने की खबरें भी सामने आईं। अक्टूबर 2026 के पहले सप्ताह में लंबी छुट्टियों के दौरान यहां आने वालों की संख्या में उल्लेखनीय उछाल की रिपोर्ट प्रकाशित हुईं।

इंडियन एक्सप्रेस की 5 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, नैनीताल के जिलाधिकारी ने बताया कि कैंची धाम में सामान्य दिनों में लगभग 25,000 श्रद्धालुओं के आने की अपेक्षा रहती है, जबकि उस लंबे अवकाश के दौरान प्रतिदिन 35,000 से अधिक लोगों की भीड़ पहुंची। इससे आसपास की पहाड़ी सड़कों पर यातायात बाधित हुआ।

इंडिया टुडे ने 4 अक्टूबर को रिपोर्ट किया कि फिल्म की सफलता के बाद कैंची धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी दिखाई दी। यातायात इतना प्रभावित हुआ कि स्थानीय लोगों, आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहनों और एंबुलेंस को भी परेशानी हुई।

इन रिपोर्टों से फिल्म की लोकप्रियता और कैंची धाम में बढ़ती भीड़ के बीच संबंध का संकेत मिलता है। हालांकि, श्रद्धालुओं की संख्या पर लंबी छुट्टियों, मौसम, धार्मिक आस्था और सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो का भी प्रभाव हो सकता है। इसलिए पूरी वृद्धि को केवल फिल्म का परिणाम बताने के बजाय इसे कई संभावित कारणों से जोड़कर देखना अधिक तथ्यपरक होगा।

फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने भी भीड़ की स्थिति को देखते हुए श्रद्धालुओं से यात्रा से पहले हालात की जानकारी लेने और जरूरत पड़ने पर बाबा से जुड़े अन्य आध्यात्मिक स्थलों पर जाने की अपील की थी। इस अपील का उल्लेख एनडीटीवी की 5 अक्टूबर की रिपोर्ट में भी हुआ।

यह घटनाक्रम बताता है कि जब किसी धार्मिक व्यक्तित्व की चर्चा अचानक बड़े स्तर पर बढ़ती है, तो उसका प्रभाव केवल सिनेमाघरों तक सीमित नहीं रहता। लोगों की यात्रा संबंधी योजनाएं, स्थानीय परिवहन और धार्मिक स्थलों की व्यवस्थाएं भी इससे प्रभावित हो सकती हैं।

आस्था का आकर्षण या सोशल मीडिया का प्रभाव?

कैंची धाम में बढ़ती भीड़ को समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि आज धार्मिक स्थलों की लोकप्रियता किस तरह विकसित होती है।

पहले किसी आश्रम या मंदिर की प्रसिद्धि स्थानीय श्रद्धालुओं, धार्मिक यात्राओं और मौखिक परंपरा के माध्यम से फैलती थी। आज फिल्मों, डिजिटल वीडियो, ऑनलाइन चर्चाओं और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किसी स्थान के बारे में जानकारी बहुत तेजी से बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सकती है।

'हनुमान अंश' ने बाबा के जीवन से जुड़े प्रसंगों को ऐसे दर्शकों तक पहुंचने का अवसर दिया, जो शायद पहले उनके बारे में सीमित जानकारी रखते थे। फिल्म देखने के बाद कुछ दर्शकों में बाबा के आश्रम और उनसे जुड़े स्थलों को देखने की जिज्ञासा पैदा होना स्वाभाविक है।

लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी धार्मिक स्थल पर जाने का निर्णय हर व्यक्ति के लिए अलग कारणों से जुड़ा हो सकता है। कोई श्रद्धा से जाता है, कोई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रुचि से, तो कोई फिल्म या सोशल मीडिया से प्रभावित होकर। इसलिए बढ़ती भीड़ को केवल चमत्कार, प्रचार या फिल्म की सफलता से समझना अधूरा होगा। यह आस्था, जनसंचार और पर्यटन के आपसी संबंध को समझने का भी विषय है।

जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़े, तो व्यवस्था की जिम्मेदारी भी बढ़ती है

कैंची धाम की बढ़ती लोकप्रियता के साथ एक महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है—क्या किसी धार्मिक स्थल का बुनियादी ढांचा अचानक बढ़ने वाली भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त है?

पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें सीमित होती हैं। पार्किंग, पैदल मार्ग, पेयजल, स्वच्छता, आपातकालीन चिकित्सा और यातायात नियंत्रण जैसी सुविधाओं पर अधिक दबाव पड़ सकता है।

यदि हजारों लोग एक ही समय पर किसी संकरे मार्ग या आश्रम के आसपास पहुंच जाएं, तो श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय निवासियों को भी परेशानी हो सकती है। इसलिए धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ भीड़ प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना जरूरी है।



श्रद्धालुओं के लिए भी कुछ सावधानियां महत्वपूर्ण हैं:

- यात्रा से पहले स्थानीय प्रशासन और आश्रम की ओर से जारी निर्देशों की जानकारी लें।

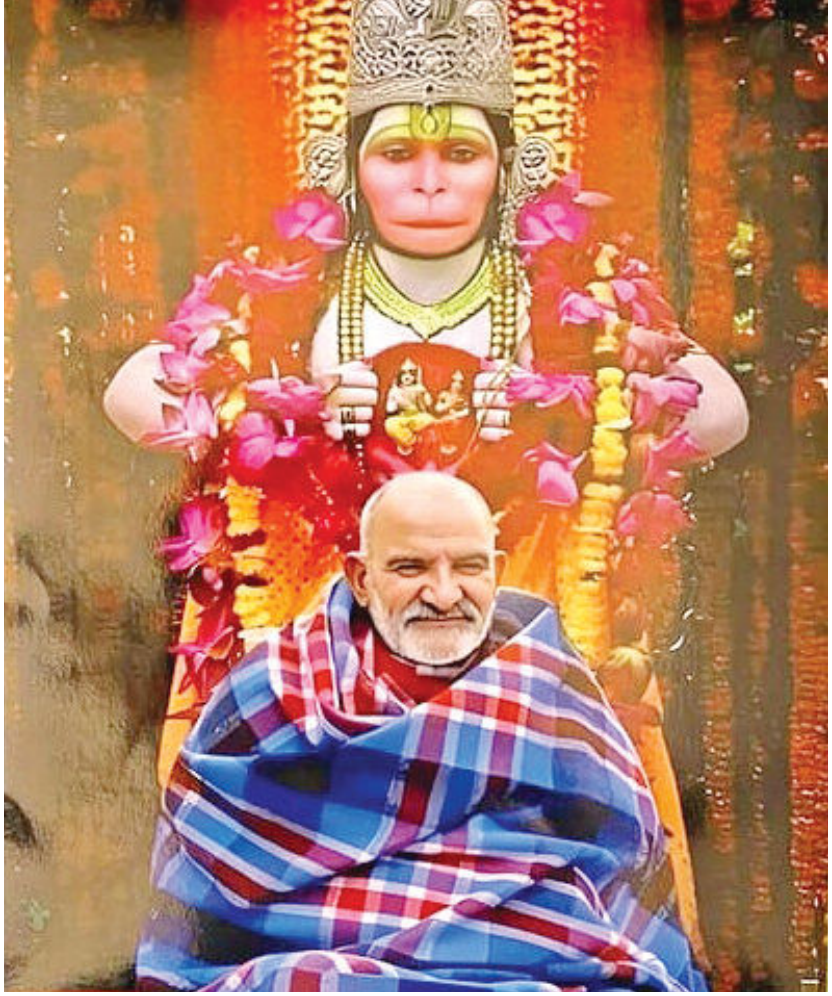
- भीड़ के समय यातायात नियमों का पालन करें और सड़क पर अनावश्यक वाहन खड़े न करें। - बुजुर्गों, बच्चों और जरूरतमंद लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखें।

- आश्रम और आसपास के प्राकृतिक क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखें।

- दर्शन को जल्दबाजी या भीड़ में धक्का-मुक्की का विषय न बनाएं।

आखिरकार, धार्मिक स्थल की गरिमा केवल दर्शन करने वालों की संख्या से नहीं, बल्कि वहां बनाए रखे गए अनुशासन, सेवा और सम्मान से भी जुड़ी होती है।







सिनेमा किसी संत की विरासत को कितनी दूर तक पहुंचा सकता है?

'हनुमान अंश' की सफलता से एक बात पर विचार किया जा सकता है—सिनेमा किसी ऐसे व्यक्तित्व को नई पीढ़ी के सामने ला सकता है, जिसके जीवन और शिक्षाओं के बारे में बहुत से लोगों को पहले सीमित जानकारी रही हो।

लेकिन किसी फिल्म की लोकप्रियता और किसी संत की शिक्षाओं को वास्तव में समझना दो अलग बातें हैं। फिल्म दर्शक के मन में जिज्ञासा पैदा कर सकती है; इसके बाद उस व्यक्ति के जीवन, विचारों और ऐतिहासिक संदर्भों को जानने की जिम्मेदारी पाठक और दर्शक की भी है।

बाबा की शिक्षाओं का मूल भाव यदि प्रेम, सेवा और करुणा है, तो उनका प्रभाव केवल मंदिर में दर्शन करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। समाज में जरूरतमंदों की सहायता, भूखों को भोजन, बुजुर्गों का सम्मान और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता भी इन मूल्यों को व्यवहार में उतारने के तरीके हैं। यही वह बिंदु है जहां धार्मिक आस्था और सामाजिक जिम्मेदारी एक-दूसरे से जुड़ती हैं।

निष्कर्ष: फिल्म की लोकप्रियता से आगे, बाबा की शिक्षाओं का सवाल

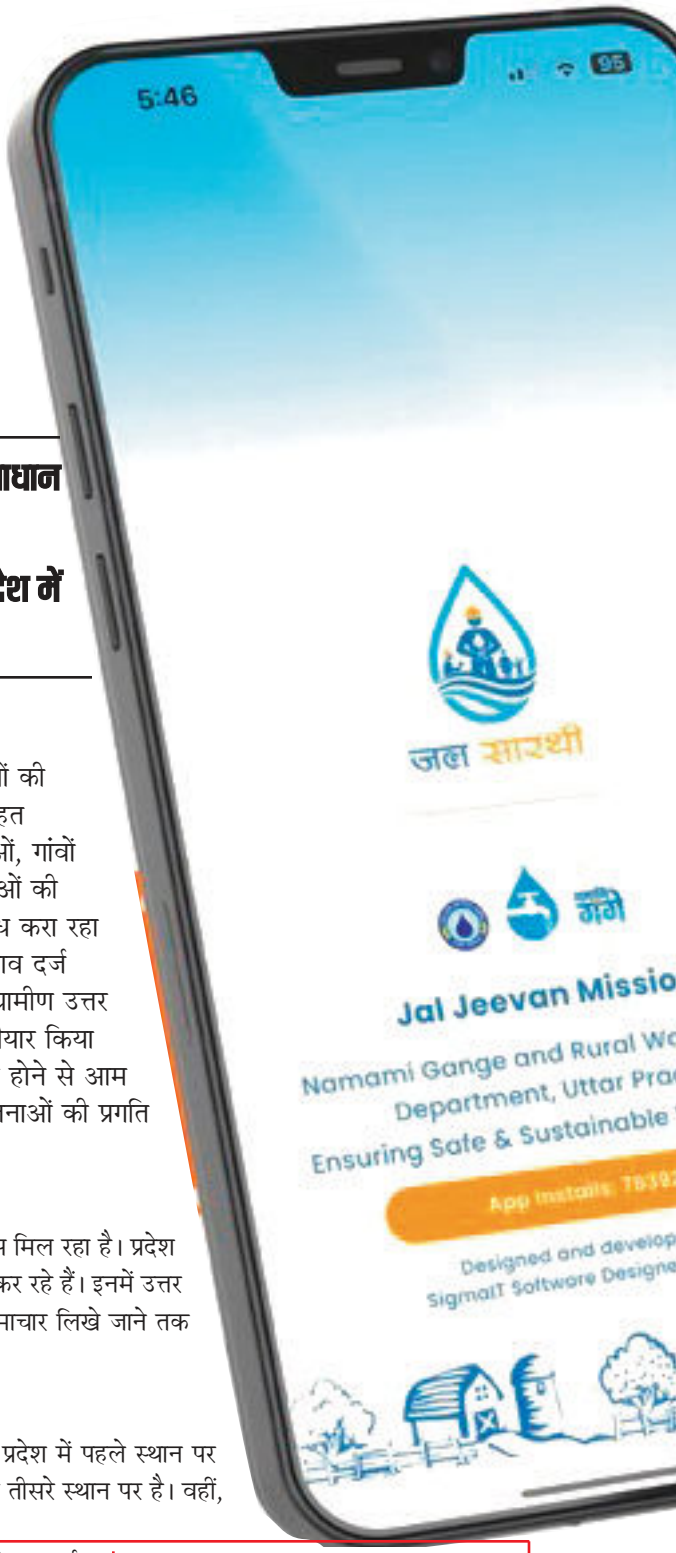
'हनुमान अंश' ने नीम करौली बाबा के जीवन से प्रेरित कहानी को व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाया है। फिल्म की कमाई और कैंची धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ इस घटनाक्रम के दो चर्चित पहलू हैं। लेकिन इस पूरे प्रसंग का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इसके माध्यम से बाबा की शिक्षाओं पर फिर से चर्चा हो रही है।

किसी संत की विरासत को केवल उनके नाम से जुड़े चमत्कारों, लोकप्रियता या करोड़ों की कमाई के आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता। उनकी शिक्षाओं का सामाजिक महत्व इस बात में भी दिखाई देता है कि लोग उनसे प्रेरित होकर अपने जीवन में क्या बदलाव लाते हैं। यदि फिल्म देखने के बाद कोई व्यक्ति कैंची धाम जाता है और वहां दर्शन करता है, तो वह उसकी आस्था का विषय है। यदि वही व्यक्ति बाबा की सेवा-भावना से प्रेरित होकर किसी भूखे को भोजन कराता है, जरूरतमंद की मदद करता है या किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करने से बचता है, तो यह उन शिक्षाओं का सामाजिक विस्तार है। फिल्में किसी संत की कहानी को लोकप्रिय बना सकती हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं का वास्तविक प्रभाव तब दिखाई देता है, जब प्रेम, सेवा और करुणा हमारे व्यवहार का हिस्सा बनते हैं। नीम करौरी बाबा की विरासत को समझने का शायद यही सबसे सार्थक तरीका है—आस्था का सम्मान करते हुए तथ्यों को जानना और आध्यात्मिक संदेश को मानवीय व्यवहार में उतारने का प्रयास करना।

गांवों में पेयजल आपूर्ति से जुड़े हर सवाल का जवाब

जलसारथी ऐप

- **पेयजल योजनाओं की निगरानी से लेकर शिकायतों के समाधान तक एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी जानकारी**
- **अंबेडकरनगर के लोग जलसारथी ऐप के इस्तेमाल में प्रदेश में अव्वल, सिद्धार्थनगर दूसरे और गाजीपुर तीसरे स्थान पर**



ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति से जुड़ी जानकारी अब लोगों की पहुंच से दूर नहीं है। जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश के तहत विकसित जलसारथी मोबाइल ऐप ग्रामीण पेयजल योजनाओं, गांवों में जलापूर्ति की स्थिति, हर घर नल कनेक्शन, परियोजनाओं की प्रगति और जल अवसंरचना से जुड़ी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा रहा है। इसके साथ ही नागरिक इस ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत और सुझाव दर्ज करने के साथ उनकी स्थिति को ट्रैक भी कर सकते हैं। जलसारथी ऐप को ग्रामीण उत्तर प्रदेश में पेयजल योजनाओं की पारदर्शी और प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। ऐप पर ग्राम, पंचायत, जिला और राज्य स्तर की जानकारी उपलब्ध होने से आम नागरिकों के साथ-साथ अधिकारी, इंजीनियर और निगरानी एजेंसियां भी योजनाओं की प्रगति पर नजर रख सकती हैं।

3.47 लाख से अधिक लोग कर रहे ऐप का उपयोग

जलसारथी ऐप को उत्तर प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों में भी लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। प्रदेश तथा दूसरे राज्यों को मिलाकर लगभग 3,47,823 लोग जलसारथी ऐप का उपयोग कर रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ दूसरे राज्यों के लोग भी शामिल हैं। ये आंकड़े समाचार लिखे जाने तक के हैं।

अंबेडकरनगर सबसे आगे

जलसारथी ऐप के उपयोग के मामले में अंबेडकरनगर 16,224 यूजर्स के साथ प्रदेश में पहले स्थान पर है। सिद्धार्थनगर 11,831 यूजर्स के साथ दूसरे और गाजीपुर 11,178 यूजर्स के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर करीब 51,420 लोगों ने ऐप इंस्टॉल किया है।

एक ऐप, पेयजल से जुड़ी पूरी जानकारी

जलसारथी ऐप पर ग्रामीण पेयजल योजनाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध हैं। इसमें ग्रामवार जलापूर्ति की स्थिति, जिला स्तर पर योजनाओं की प्रगति, ग्राम पंचायत स्तर का डैशबोर्ड, चल रही

कुल ऐप यूजर्सः	3,47,823
अंबेडकरनगरः	16,224 यूजर्स (प्रदेश में प्रथम स्थान)
सिद्धार्थनगरः	11,831 यूजर्स (प्रदेश में द्वितीय स्थान)
गाजीपुरः	11,178 यूजर्स (प्रदेश में तृतीय स्थान)
अन्य राज्य :	51,420 यूजर्स



परियोजनाओं की स्थिति और जल अवसंरचना की निगरानी की सुविधा शामिल है। इसके अलावा ऐप के माध्यम से हर घर नल से जल योजना के तहत घरेलू नल कनेक्शन से जुड़े आंकड़े, जीआईएस मैपिंग, जल परिसंपत्तियों की जानकारी और ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं की जमीनी स्थिति भी देखी जा सकती है।

शिकायत दर्ज करने के साथ ट्रैकिंग की सुविधा

जलसारथी ऐप की एक महत्वपूर्ण सुविधा यह भी है कि नागरिक पेयजल आपूर्ति से संबंधित शिकायत और सुझाव दर्ज कर सकते हैं तथा उनकी स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। इससे शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सभी लोग कर सकते हैं उपयोग

जलसारथी ऐप को अलग-अलग वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। इसका उपयोग आम नागरिक, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, इंजीनियर, क्षेत्रीय कर्मचारी और निगरानी एजेंसियां कर सकती हैं। बहुस्तरीय डैशबोर्ड के माध्यम से राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर योजनाओं की स्थिति का अवलोकन किया जा सकता है।

प्रबंध निदेशक ने अधिक से अधिक लोगों से ऐप इंस्टॉल करने की अपील की

जल निगम ग्रामीण के प्रबंध निदेशक योगेश कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाना विभाग की प्राथमिकता है। जल निगम ग्रामीण का सीधा संबंध गांवों और ग्रामीणों की पेयजल जरूरतों से है। इसी को ध्यान में रखते हुए जलसारथी ऐप तैयार किया गया है, ताकि लोगों को पेयजल योजनाओं और आपूर्ति से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सके।

उन्होंने कहा कि विभाग का प्रयास है कि अधिक से अधिक ग्रामीण जलसारथी ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें और इसका उपयोग करें। इससे लोगों को अपने गांव की पेयजल व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करने के साथ ही शिकायत और सुझाव दर्ज करने की सुविधा भी मिलेगी।

एक नजर में आंकड़े (समाचार लिखे जाने तक)


शहनाज इलियास
SHAHNAZ ILLYAS

आजादी के 80 साल और सामाजिक न्याय का टूटता ताला

वर्ष 2027 चल रहा है। भारत अपनी आजादी के 80वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। एक तरफ हमारा देश 'सेंसेक्स' की नई ऊंचाइयों, 6G कनेक्टिविटी, एआई (AI) और अंतरिक्ष अभियानों के जरिए वैश्विक महाशक्ति बनने की हुंकार भर रहा है; वहीं दूसरी तरफ, सामाजिक असमानता की एक कड़वी और आदिम हकीकत आज भी हमारा पीछा कर रही है। अक्टूबर 2026 में तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले के कुराल गांव से आई एक खबर ने देश के इस आधुनिक चमक-दमक वाले चेहरे पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। यहाँ के श्री कलियुग श्रीनिवास पेरुमल मंदिर में जब दलित समुदाय (आदि द्रविड़) के लोग श्रद्धा की थालियां लेकर पहुंचे, तो तथाकथित उच्च जाति के लोगों ने सामाजिक समरसता की धज्जियां उड़ाते हुए मंदिर के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया।

सवाल यह उठता है कि आठ दशकों की आजादी और लोकतांत्रिक परिपक्वता के बाद भी, क्या इस देश के एक नागरिक की आस्था का सम्मान इस बात से तय होगा कि वह किस जाति में पैदा हुआ है?

शहनाज इलियास का साहस: जब प्रशासनिक इच्छाशक्ति ने तोड़ी जड़ता

इस तनावपूर्ण और विस्फोटक माहौल के बीच कल्लाकुरिची जिले की पुलिस अधीक्षक (SP) शहनाज इलियास (IPS) पुलिस बल के साथ खुद मौके पर पहुंचीं। उन्होंने किसी राजनीतिक नफे-नुकसान या सामाजिक तनाव के तथाकथित 'खतरे' की परवाह नहीं की। उन्होंने संविधान की सर्वोच्चता को तरजीह दी और खुद आगे बढ़कर मंदिर का ताला खुलवाया। वे सिर्फ द्वार खोलकर नहीं रुकीं, बल्कि दलित समुदाय के लोगों को सुरक्षा घेरे में ससम्मान गर्भगृह के भीतर ले गईं और उनकी पूजा सुनिश्चित कराई।

यह घटना भारतीय प्रशासनिक सेवा के इतिहास में एक शानदार मिसाल है। लेकिन इस सराहना के पीछे छिपा आत्ममंथन का सवाल और भी गहरा है। कल्लाकुरिची के इस मंदिर में दलितों का प्रवेश पिछले 50 वर्षों से वर्जित था। इस आधी सदी के दौरान वहाँ न जाने कितने जिला कलेक्टर, पुलिस कप्तान और प्रशासनिक अधिकारी आए और गए होंगे। मंदिर की वे दीवारें और समाज के बीच खिंची वह अदृश्य भेदभाव की लकीर रातों-रात तो नहीं बनी थी। तो फिर शहनाज इलियास से पहले किसी अधिकारी ने इस 50 साल पुराने ताले को तोड़ने की हिम्मत क्यों



नहीं दिखाई? क्या हमारा प्रशासनिक अमला 'शांति व्यवस्था' बनाए रखने के नाम पर इस अमानवीय भेदभाव को मूक सहमति देता रहा था? यह वाकया साफ करता है कि सामाजिक बदलाव के लिए सिर्फ कानून की किताबों की नहीं, बल्कि उसे जमीन पर उतारने वाले मजबूत इरादों की जरूरत होती है।

देश के मंदिरों का इतिहासः संघर्ष, कानून और जमीनी सच

श्री कलियुग श्रीनिवास पेरुमल मंदिर, कल्लाकुरिची (तमिलनाडु)

समस्याः इस मंदिर में पिछले 50 वर्षों से दलितों के प्रवेश पर अघोषित रोक थी। अक्टूबर 2026 में जब दलित समुदाय के लोग पूजा करने पहुंचे, तो रूढ़िवादी तत्वों ने मंदिर के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया।

सुधारः एसपी शहनाज इलियास ने खुद मौके पर पहुंचकर पुलिस बल के साथ ताला तुड़वाया और पुलिस सुरक्षा के बीच दलित समुदाय को गर्भगृह में प्रवेश कराकर पूजा संपन्न कराई।

वायकोम व गुरुवायूर मंदिर (केरल)

समस्याः यहाँ अछूत माने जाने वाले वर्गों को मंदिर के गर्भगृह में जाना तो दूर, मंदिर के आस-पास की सार्वजनिक सड़कों पर कदम रखने की भी इजाजत नहीं थी।

सुधारः वर्ष 1924-25 में महात्मा गांधी, पेरियार और टी.के. माधवन के नेतृत्व में ऐतिहासिक 'वायकोम सत्याग्रह' हुआ। इसके चौतरफा दबाव में 1936 में त्रावणकोर के महाराजा ने 'मंदिर प्रवेश उद्घोषणा' जारी कर सभी हिंदुओं के लिए दरवाजे खोले।

कालाराम मंदिर, नासिक (महाराष्ट्र)

समस्याः इस ऐतिहासिक और प्रमुख राम मंदिर में निचली जाति के लोगों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित था, जिससे समाज के एक बड़े हिस्से में भारी असंतोष और पीड़ा थी।

सुधारः डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने 2 मार्च 1930 को यहाँ एक विशाल सत्याग्रह शुरू किया। इस कड़े और लंबे वैचारिक व जमीनी संघर्ष के बाद आज यहाँ बिना किसी भेदभाव के हर भारतीय नागरिक पूजा करता है।

जगन्नाथ मंदिर, पुरी (ओडिशा)

समस्याः प्राचीन और मध्यकाल में स्थानीय व्यवस्था के तहत निचली जातियों के प्रवेश पर कड़ी पाबंदियां और शुद्धिकरण के कठोर नियम लागू थे।

सुधारः आजादी के बाद कानूनी रूप से यह सभी सनातनी हिंदुओं के लिए खोल दिया गया। हालांकि, गैर-हिंदुओं और विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर आज भी पारंपरिक प्रतिबंध लागू है, लेकिन जातिगत भेदभाव अब यहाँ पूरी तरह खत्म हो चुका है।

पर्वतीय क्षेत्रों के मंदिर, उत्तराखंड (जैसे महासू देवता व स्थानीय देवस्थान)

समस्याः जौनसार-बावर और सुदूर हिमालयी गांवों के कुछ देवस्थानों में आज भी पारंपरिक और रूढ़िवादी मान्यताओं के नाम पर दलितों को मुख्य परिसर या गर्भगृह से दूर रखने की कोशिश की जाती है।

सुधार (चुनौतियां आज भी जारी): हालांकि कानूनन ऐसा करना अपराध है, लेकिन भौगोलिक रूप से सुदूर इलाकों में आज भी जागरूकता की कमी के कारण छिटपुट भेदभाव की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिन्हें प्रशासन और सामाजिक संगठन बलपूर्वक व समझाइश से ठीक कराते हैं।

सूचना और कानूनी सुरक्षा ढांचा

भारतीय संविधान निर्माताओं ने भली-भांति भांप लिया था कि बिना सामाजिक समानता के राजनीतिक आजादी अधूरी है। इसीलिए देश में एक मजबूत कानूनी सुरक्षा ढांचा तैयार किया गयाः

संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 17 और 15): भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता (छुआछूत) को पूरी तरह समाप्त करता है और इसका किसी भी रूप में आचरण



दंडनीय अपराध घोषित करता है। वहीं, अनुच्छेद 15(2) साफ कहता है कि किसी भी नागरिक को उसकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक इबादतगाहों में जाने से नहीं रोका जा सकता।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955: इसके तहत यदि कोई व्यक्ति किसी को धार्मिक स्थल, घाट या सार्वजनिक जलाशय आदि का उपयोग करने से जाति के आधार पर रोकता है, तो वह कानूनी तौर पर जेल और जुर्माने का भागीदार है।

SC/ST **(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989**: यह कानून अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के खिलाफ होने वाले सामाजिक भेदभाव और अत्याचार को समूल नष्ट करने के लिए बनाया गया है। कल्लाकुरिची जैसी घटनाओं में शामिल दोषियों के खिलाफ इसी कड़े कानून के तहत गैर-जमानती मामले दर्ज किए जाते हैं। जब तक मन का ताला नहीं टूटेगा... आजादी के 80वें साल में हमें यह समझना होगा कि भारत तब तक असल मायनों में 'विश्वगुरु' नहीं बन सकता, जब तक समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भगवान के दरबार में सम्मान पाने के लिए किसी पुलिस कप्तान के हथौड़े का इंतजार करना पड़े। कानून ने सदियों पुराने बंद दरवाजे तोड़ दिए हैं, अब हमारे समाज को अपने मन के कपाट खोलने होंगे। शहनाज इलियास का आधिकारिक बयान_ घटनास्थल पर जब कुछ रूढ़िवादी तत्वों और महिलाओं ने मंदिर के दरवाजे पर बैठकर यह दावा किया कि, मैडम, यह हमारा (हमारी जाति का) मंदिर है, तब पुलिस अधीक्षक शहनाज इलियास ने कानून का पाठ पढ़ाते हुए दोटूक शब्दों में कहा_क्या यह मंदिर आपके व्यक्तिगत नाम पर रजिस्टर्ड है? यह अब एक सार्वजनिक मंदिर है जिसे HR&CE (हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग) द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ किसी भी नागरिक को उसकी जाति या वंश के आधार पर पूजा करने से नहीं रोका जा सकता।

जब भीड़ में से किसी व्यक्ति ने उनके इस आदेश पर तंज कसने की कोशिश की, तो उन्होंने अपनी प्रशासनिक धमक दिखाते हुए सीधे ललकारा, अगर तुममें इतनी ही हिम्मत है, तो सामने आओ और मेरे सामने यह बात कहकर दिखाओ। कानून की इस कड़क आवाज के सामने विरोध कर रही भीड़ पूरी तरह खामोश हो गई और वह ताला टूट गया जो पिछले 50 सालों से सामाजिक न्याय को रोके हुए था।




श्रुति श्रीवास्तव
SHRUTI SRIVASTAVA

24 साल की उम्र में UPSC में 82वीं रैंक हासिल करने वाली श्रुति श्रीवास्तव की प्रेरक कहानी

दिल्ली के हिंदू कॉलेज से JNU तक पढ़ाई, लोकसभा सचिवालय में नौकरी, बिना कोचिंग सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी और फिर उत्तर प्रदेश पुलिस में अहम जिम्मेदारी। जानिए IPS श्रुति श्रीवास्तव की वह यात्रा, जो युवाओं को अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहने की प्रेरणा देती है।

सफलता की कहानियां अक्सर किसी बड़े सपने से शुरू होती हैं, लेकिन हर सफल व्यक्ति को शुरुआत से ही यह पता हो, यह जरूरी नहीं कि उसे जीवन में क्या बनना है। कई बार एक सलाह, एक अनुभव और अपने भीतर छिपी क्षमताओं को पहचानने का अवसर जीवन की दिशा बदल देता है। भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी श्रुति श्रीवास्तव की कहानी भी इसी बात को रेखांकित करती है। कभी शिक्षण के क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाली श्रुति ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 82वीं रैंक हासिल की और भारतीय पुलिस सेवा में जगह बनाई। आज वह उत्तर प्रदेश कैडर की 2020 बैच की IPS अधिकारी हैं और प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त (Additional DCP) की जिम्मेदारी संभाल रही हैं।

उनकी यात्रा केवल एक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की कहानी नहीं है। इसमें उच्च शिक्षा, करियर को लेकर बदलती प्राथमिकताएं, नौकरी के साथ तैयारी और लगातार प्रयास करने की सीख भी छिपी है।

दिल्ली से शुरू हुआ सफर

उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, श्रुति श्रीवास्तव का जन्म 3 नवंबर 1995 को हुआ था। वह दिल्ली की रहने वाली हैं और उनके पिता का नाम संजय श्रीवास्तव है।

उनकी शैक्षणिक यात्रा दिल्ली से शुरू हुई। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने NET-JRF भी उत्तीर्ण किया था।

अंग्रेजी साहित्य और शिक्षण में रुचि रखने वाली श्रुति के लिए अकादमिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का विकल्प स्वाभाविक था। कॉलेज के दिनों में उनका लक्ष्य भारतीय पुलिस सेवा में जाना नहीं था। वह प्रोफेसर बनकर पढ़ाने के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती थीं।

लेकिन जीवन में कई बार मंजिल तक पहुंचने का रास्ता किसी अप्रत्याशित मोड़ से होकर गुजरता है। श्रुति के मामले में भी ऐसा ही हुआ।

एक सलाह ने बदल दी करियर की दिशा

श्रुति श्रीवास्तव ने अपनी UPSC यात्रा के बारे में एक बातचीत में बताया था कि कॉलेज के दिनों में सिविल सेवा में जाने की उनकी कोई निश्चित योजना नहीं थी। वह शिक्षण के क्षेत्र में करियर बनाना चाहती थीं।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एक वरिष्ठ विद्यार्थी की सलाह के बाद उन्होंने सिविल सेवा को गंभीरता से समझना शुरू किया। धीरे-धीरे उन्हें महसूस हुआ कि उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और क्षमताओं का उपयोग प्रशासनिक सेवा में भी किया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने UPSC की तैयारी की दिशा में कदम बढ़ाया।

यह प्रसंग उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो करियर को लेकर असमंजस में रहते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति की सलाह रास्ता दिखा सकती है, लेकिन उस रास्ते पर चलने का निर्णय स्वयं लेना पड़ता है। श्रुति ने भी सलाह मिलने के बाद तैयारी शुरू की और आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयास किए।

JNU की पढ़ाई के साथ UPSC की तैयारी

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में गिनी जाती है। इसमें सामान्य अध्ययन, विश्लेषणात्मक क्षमता, लेखन कौशल, वैकल्पिक विषय और साक्षात्कार सहित कई स्तरों पर अभ्यर्थियों की तैयारी परखी जाती है।

श्रुति श्रीवास्तव ने UPSC की तैयारी के दौरान शुरुआती दो प्रयास JNU में पढ़ाई करते हुए किए। इन प्रयासों के बाद भी उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने इसके बाद लोकसभा सचिवालय में लगभग दो वर्षों तक काम किया और नौकरी के साथ परीक्षा की तैयारी जारी रखी।

यह उनकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पढ़ाई के साथ नौकरी की जिम्मेदारी निभाते हुए किसी कठिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना समय और अनुशासन की मांग करता है।

नौकरी के साथ तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के सामने सीमित समय, नियमित अध्ययन और परीक्षा की रणनीति बनाए रखने जैसी चुनौतियां होती हैं। श्रुति की कहानी इस बात का उदाहरण है कि करियर के एक चरण में काम करते हुए भी किसी बड़े लक्ष्य के लिए प्रयास जारी रखे जा सकते हैं।

बिना कोचिंग तीसरे प्रयास में

हासिल की 82वीं रैंक

श्रुति श्रीवास्तव ने वर्ष 2019 की UPSC सिविल सेवा परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 82वीं रैंक हासिल की। उस समय उनकी उम्र लगभग 24 वर्ष थी। उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर आवंटित हुआ और वह भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुईं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने बिना किसी औपचारिक कोचिंग संस्थान पर निर्भर हुए परीक्षा की तैयारी की। उनकी तैयारी में NCERT की किताबों, पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन के अभ्यास को महत्व दिया गया।

यहां उनकी सफलता का अर्थ यह नहीं है कि कोचिंग की जरूरत किसी भी अभ्यर्थी को नहीं पड़ती। प्रत्येक विद्यार्थी की परिस्थितियां, अध्ययन शैली और जरूरतें अलग होती हैं। उनकी यात्रा से मिलने वाली सीख यह है कि उपलब्ध संसाधनों का सही इस्तेमाल, नियमित अभ्यास और अपनी कमजोरियों को पहचानना तैयारी को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है।

उनकी सफलता उन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से प्रेरक हो सकती है, जो महंगी कोचिंग या सीमित संसाधनों को अपने लक्ष्य के रास्ते की बड़ी बाधा मानते हैं।

IPS प्रशिक्षण में भी दिखाई प्रतिभा

सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के बाद अधिकारी का प्रशिक्षण शुरू होता है। इस दौरान केवल प्रशासनिक और पुलिस संबंधी ज्ञान ही नहीं, बल्कि शारीरिक क्षमता, अनुशासन, नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान दिया जाता है।

श्रुति श्रीवास्तव ने हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण लिया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने योग के लिए 'गांधी ज्ञान मंदिर योग केंद्र ट्रॉफी' भी जीती थी।

यह उपलब्धि उनके व्यक्तित्व के एक दूसरे पक्ष को सामने लाती है। पुलिस सेवा में कार्य करने वाले अधिकारियों के लिए मानसिक संतुलन, शारीरिक सक्रियता और अनुशासन महत्वपूर्ण हैं। योग जैसी गतिविधियां नियमित अभ्यास, एकाग्रता और आत्मनियंत्रण की आदत विकसित करने में सहायक हो सकती हैं।

हालांकि, किसी अधिकारी की कार्यक्षमता का आकलन केवल एक पुरस्कार से नहीं किया जा सकता। इसके लिए उनके पेशेवर काम, निर्णय क्षमता और सार्वजनिक जिम्मेदारियों के निर्वहन को भी देखना जरूरी है।

उत्तर प्रदेश पुलिस में जिम्मेदारियों का सफर

श्रुति श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश कैडर की 2020 बैच की IPS अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक रिकॉर्ड में उनकी भर्ती की तारीख 28 दिसंबर 2020 और वर्तमान पद अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज दर्ज है। रिकॉर्ड में उनकी प्रयागराज में तैनाती की तारीख 19 सितंबर 2026 दी गई है।

इससे पहले वह वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त के पद पर तैनात थीं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वह कानपुर नगर में भी सेवाएं दे चुकी हैं।

पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था में अपर पुलिस उपायुक्त का पद शहर की पुलिस व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अधिकारियों को अपने निर्धारित क्षेत्र और कार्य-विभाजन के अनुसार कानून-व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और अन्य जिम्मेदारियों के निर्वहन में भूमिका निभानी होती है। प्रयागराज जैसे शहर में पुलिस की जिम्मेदारियों का महत्व और बढ़ जाता है। यहां धार्मिक आयोजनों, बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों, यातायात और शहरी कानून-व्यवस्था से जुड़े विषयों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। हालांकि, श्रुति श्रीवास्तव के व्यक्तिगत कार्य-विभाजन और उनके अधीन आने वाले विभागों की पुष्टि संबंधित आधिकारिक आदेश से की जानी चाहिए।

उनकी नई तैनाती उनके सेवा-करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस पद पर उनकी भूमिका और कार्यों का वास्तविक मूल्यांकन उनके कार्यकाल के दौरान सामने आने वाले परिणामों के आधार पर किया जा केगा।

महाकुंभ के दौरान रवीना टंडन के इंटरव्यू को लेकर भी चर्चा

श्रुति श्रीवास्तव की चर्चा केवल उनकी UPSC सफलता और पुलिस सेवा तक सीमित नहीं रही। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान अभिनेत्री रवीना टंडन से उनके संवाद और इंटरव्यू को लेकर भी खबरें सामने आई थीं। अमर उजाला की रिपोर्ट में इस प्रसंग का उल्लेख उनके प्रयागराज में नई तैनाती की खबर के साथ किया गया था।

इस प्रसंग ने उनके सार्वजनिक परिचय को एक अलग आयाम दिया। हालांकि, किसी अधिकारी की पहचान को केवल किसी चर्चित व्यक्ति के इंटरव्यू या सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। उनकी प्राथमिक पहचान एक लोकसेवक की है, जिसकी जिम्मेदारी कानून के दायरे में जनता की सुरक्षा और प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना है।

उनकी कहानी से युवाओं को क्या सीख मिलती है?

श्रुति श्रीवास्तव की यात्रा से कई व्यावहारिक बातें सामने आती हैं।

पहली सीख—करियर की दिशा बदलना असफलता नहीं है। उन्होंने शिक्षण के क्षेत्र में जाने की इच्छा से शुरुआत की, लेकिन बाद में सिविल सेवा को अपना लक्ष्य बनाया। जीवन में नई संभावनाओं को समझना और अपने निर्णय पर काम करना महत्वपूर्ण है।

दूसरी सीख—एक प्रयास में सफलता न मिले तो तैयारी की समीक्षा करें। उनकी UPSC सफलता तीसरे प्रयास में आई। यह याद दिलाता है कि किसी कठिन परीक्षा में परिणाम आने से पहले अपनी रणनीति सुधारने और कमजोरियों पर काम करने का अवसर होता है।

तीसरी सीख—संसाधनों से अधिक महत्वपूर्ण उनका सही इस्तेमाल है। बिना कोचिंग तैयारी करने का उनका उदाहरण दिखाता है कि किताबों, प्रश्नपत्रों और अभ्यास की मदद से भी तैयारी की जा सकती है। लेकिन इसके लिए अनुशासन और सही अध्ययन योजना जरूरी है।

चौथी सीख—शिक्षा का उपयोग अलग-अलग क्षेत्रों में किया जा सकता है। अंग्रेजी विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद पुलिस सेवा में जाना यह दर्शाता है कि किसी विषय की पढ़ाई व्यक्ति को केवल एक पेशे तक सीमित नहीं करती।

पांचवीं सीख—सफलता के बाद जिम्मेदारी शुरू होती है। UPSC में रैंक हासिल करना एक उपलब्धि है, लेकिन पुलिस अधिकारी के रूप में जनता के प्रति जवाबदेही निभाना एक अलग और निरंतर चलने वाली जिम्मेदारी है।

रैंक से आगे, जिम्मेदारी तक का सफर

IPS श्रुति श्रीवास्तव की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो अपने करियर को लेकर नए विकल्प तलाश रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

दिल्ली में पढ़ाई से लेकर JNU, लोकसभा सचिवालय में नौकरी, UPSC में 82वीं रैंक और उत्तर प्रदेश पुलिस में जिम्मेदारी तक की उनकी यात्रा कई पड़ावों से होकर गुजरी है। इस सफर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने करियर की दिशा बदली, लगातार प्रयास किया और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयारी जारी रखी।

उनकी कहानी को केवल कम उम्र में IPS बनने तक सीमित करना उचित नहीं होगा। इसका व्यापक संदेश यह है कि किसी व्यक्ति का शुरुआती सपना ही उसकी अंतिम मंजिल हो, यह जरूरी नहीं। समय के साथ नई संभावनाओं को पहचानना, निर्णय लेना और उस दिशा में मेहनत करना भी सफलता का हिस्सा है।

एक सलाह ने दिशा दिखाई, लगातार प्रयासों ने मंजिल तक पहुंचाया और अब सार्वजनिक सेवा में जिम्मेदारी निभाना उनके करियर की अगली परीक्षा है। यही वह संदेश है, जो श्रुति श्रीवास्तव की यात्रा को एक समाचार से आगे बढ़ाकर युवाओं के लिए एक प्रेरक कहानी बनाता है।

अवसर, चुनौतियां और आगे की राह

एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की ओर उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2029-30 तक अपनी अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह केवल आर्थिक उपलब्धि का लक्ष्य नहीं है, बल्कि राज्य को देश की विकास यात्रा का प्रमुख इंजन बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा भी है। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य के लिए यह लक्ष्य जितना प्रेरक है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) लगभग 30.25 लाख करोड़ रुपये के आसपास है। सरकार का अनुमान है कि चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक यह बढ़कर लगभग 36 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। इसके बाद 2026-27 से 2029-30 के बीच लगातार तेज आर्थिक विस्तार की आवश्यकता होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए राज्य को औसतन 24 से 25 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर हासिल करनी होगी, जबकि वर्तमान वृद्धि दर लगभग 13 से 14 प्रतिशत के बीच है। यही अतर सरकार के सामने सबसे बड़ी परीक्षा बनकर खड़ा है।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल सरकारी योजनाएं पर्याप्त नहीं होंगी। कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, निवेश, रोजगार, निर्यात, तकनीक और बुनियादी ढांचे में समानांतर गति से विकास सुनिश्चित करना होगा। विकास की रफ्तार तभी बढ़ेगी जब इन सभी क्षेत्रों में समन्वित और दीर्घकालिक रणनीति अपनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत उसका कृषि क्षेत्र है। राज्य देश के प्रमुख कृषि उत्पादक राज्यों में शामिल है। अब आवश्यकता केवल उत्पादन बढ़ाने की नहीं, बल्कि कृषि को मूल्य संवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण, आधुनिक तकनीक और निर्यात से जोड़ने की है। यदि किसानों को बेहतर बाजार, प्रसंस्करण इकाइयों और आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला का लाभ मिलता है तो कृषि राज्य की आर्थिक वृद्धि का मजबूत आधार बन सकती है। विनिर्माण क्षेत्र को भी नई गति देने पर सरकार का विशेष जोर है। विभिन्न औद्योगिक कॉरिडोर, रक्षा औद्योगिक गलियारा, एक्सप्रेस-वे आधारित औद्योगिक विकास, एमएसएमई इकाइयों का विस्तार तथा नए मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टरों की स्थापना से निवेश आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि उद्योगों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं, कुशल मानव संसाधन और सरल प्रशासनिक व्यवस्था मिलती है तो रोजगार के बड़े अवसर भी सृजित होंगे। पर्यटन भी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकता है। अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज, चित्रकूट, कुशीनगर, सारनाथ और आगरा जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों के कारण राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। बेहतर सड़क, रेल और हवाई संपर्क के साथ पर्यटन अवसंरचना का विस्तार स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान कर सकता है। इससे होटल, परिवहन, हस्तशिल्प, खान-पान और अन्य सेवा क्षेत्रों में भी व्यापक रोजगार उत्पन्न होगा। सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। डेटा सेंटर, आईटी पार्क, स्टार्टअप इकोसिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को प्रोत्साहन देकर सरकार नए निवेश आकर्षित करना चाहती है। युवाओं की बड़ी आबादी को तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ना इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार वर्ष 2047 के लिए विकसित उत्तर प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार करा रही है। इसमें छह ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तथा प्रति व्यक्ति आय को लगभग 36 लाख रुपये तक पहुंचाने का दीर्घकालिक लक्ष्य रखा गया है। यह दस्तावेज केवल भविष्य की कल्पना नहीं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने का आधार बनेगा। इसके अल्पकालिक लक्ष्यों से भी एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण सहायता मिलने की उम्मीद है। हालांकि इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के सामने कई चुनौतियां भी हैं। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, निवेश प्रवाह में उतार-चढ़ाव, महंगाई, ऊर्जा लागत और निर्यात बाजार की चुनौतियां राज्य की विकास गति को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा निवेश परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन, प्रशासनिक दक्षता, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी भी सफलता के लिए आवश्यक होगी। इसी संदर्भ में राजधानी लखनऊ में आयोजित 'लखनऊ डायलॉग-2026' में भी विशेषज्ञों ने उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा पर विस्तार से चर्चा की। गिरि विकास अध्ययन संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने कहा कि भारत को दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती के लिए संस्थागत क्षमता को और सशक्त बनाना होगा। वहीं संस्थान के निदेशक डॉ. हर्ष शर्मा ने स्पष्ट किया कि विकसित भारत का सपना उत्तर प्रदेश के तीव्र आर्थिक विकास के बिना पूरा नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश आज देश के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक है। विशाल जनसंख्या, बढ़ता शहरीकरण, बेहतर कनेक्टिविटी, एक्सप्रेस-वे नेटवर्क, नए एयरपोर्ट, औद्योगिक निवेश और डिजिटल अवसंरचना राज्य को नई आर्थिक पहचान दे रहे हैं। यदि इन प्रयासों के साथ नीति निर्माण, निवेश और रोजगार सृजन की गति बनी रहती है तो एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य केवल सरकारी घोषणा नहीं, बल्कि वास्तविक उपलब्धि में भी बदल सकता है।

स्पष्ट है कि यह लक्ष्य आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। इसके लिए सरकार, उद्योग जगत, किसानों, उद्यमियों, निवेशकों और समाज के सभी वर्गों को साझा प्रयास करने होंगे। यदि विकास की वर्तमान गति को और अधिक प्रभावी बनाया गया।

भारतीय भाषाओं का सांस्कृतिक महत्व



डॉ. सौरभ मालवीय



भारत में अनेक भाषाएं एवं बोलियां हैं। इसलिए यहां यह लोकोक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है- "कोस-कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी।" भारत की सांस्कृतिक पहचान का सबसे सशक्त एवं जीवंत आधार इसकी भाषाएं हैं। ये भाषाएं केवल संवाद का साधन मात्र नहीं हैं, अपितु ये हमारी प्राचीन सभ्यता, दर्शन, ज्ञान परंपरा, लोक जीवन, लोक कला, लोक संस्कृति, साहित्य आदि की संवाहक हैं।

भारतीय साहित्य का इतिहास विश्व के सबसे प्राचीन एवं समृद्ध साहित्यिक धरोहर में से एक है। संस्कृत को 'देववाणी' कहा जाता है, क्योंकि इसमें वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण एवं महाभारत आदि ग्रंथों की रचना हुई। आयुर्वेद, गणित, खगोल विज्ञान एवं दर्शन के मूलभूत सिद्धांत संस्कृत एवं तमिल जैसी प्राचीन भाषाओं में लिखे गए। बौद्ध एवं जैन धर्मों ने जन साधारण तक अपने संदेश पहुंचाने के लिए पाली एवं प्राकृत जैसी लोकभाषाओं का चयन किया। इसके कारण ज्ञान को जनसाधारण के लिए सर्वसुलभ बनाया गया।

भारतीय भाषाएं विविधता में एकता का प्रतीक हैं। भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण चार प्रमुख भाषा परिवारों में किया जाता है- इंडो-आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रो-एशियाटिक एवं तिब्बती-बर्मन। इंडो-आर्यन में हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती एवं पंजाबी भाषाएं सम्मिलित हैं। द्रविड़ में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एवं मलयालम भाषाएं सम्मिलित हैं। ऑस्ट्रो-एशियाटिक में संथाली एवं खासी भाषाएं सम्मिलित हैं। तिब्बती-बर्मन में मणिपुरी एवं बोडो भाषाएं सम्मिलित हैं। इन सभी भाषा वर्गों में भिन्नता अवश्य है, परंतु इनकी आत्मा एवं संस्कृति एक ही है। प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक संपर्क के कारण द्रविड़ भाषाओं के अनेक शब्द उत्तर भारतीय भाषाओं में सम्मिलित हो गए। इसी प्रकार उत्तर की भाषाओं के शब्द दक्षिण की भाषाओं में सम्मिलित हो गए।

प्रत्येक भाषा की एक संस्कृति है। स्थानीय भाषाओं से लोक कथाएं, लोकोक्तियां, लोकगीत एवं नाट्य कलाएं जन्मी हैं। हिंदी की बोली अवधी एवं ब्रज से रामलीला एवं रसलीला का जन्म हुआ। इनसे भक्ति आंदोलन एवं लोक-गाथाओं की जीवंत परंपरा को प्रोत्साहन मिला। इसी प्रकार तमिल एवं तेलुगु भाषा से यक्षगान, कत्थकली, भरतनाट्यम आदि का जन्म हुआ। इसका शास्त्रीय संगीत एवं मन्दिर संस्कृति से संबंध है। मराठी एवं गुजराती से तमाशा, लावणी, गरबा एवं भवाई का जन्म हुआ। शास्त्रीय संगीत एवं लोक उत्सवों में इनका अत्यधिक महत्व है। बांग्ला एवं असमिया से जात्रा, बीहू गीत एवं बाऊल



संगीत का जन्म हुआ। आध्यात्मिक प्रेम एवं प्रकृति सौंदर्य में इनका अत्यंत महत्व है।

मध्यकाल में भक्ति आंदोलन ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से सामाजिक क्रांति की नींव रखी। विभिन्न भाषाओं के संतों एवं कवियों ने जनभाषा में साहित्य की रचना की। इनमें कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, चंडीदास, पुरंदरदास एवं तिरुवल्लुवर आदि प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त भेदभाव एवं अंधविश्वास जैसी कुरीतियों का विरोध किया तथा ईश्वर भक्ति एवं समानता का संदेश दिया। इस प्रकार उन्होंने संपूर्ण भारत को एक सांस्कृतिक सूत्र में पिरोने का कार्य किया।

परंतु दुख का विषय है कि भारतीय भाषाओं एवं बोलियों पर लुप्त होने का संकट मंडरा रहा है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की कई संकटग्रस्त भाषाएं अपने अंतिम श्वास ले रही हैं। इस संकट के दृष्टिगत केंद्र की मोदी सरकार भाषाओं के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं को अत्यंत महत्त्व दिया जा रहा है। देश में हिंदी में चिकित्सा की पढ़ाई प्रारंभ होना भी इसी दिशा में उठाया हुआ एक पग है। इससे देश में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। लाखों छात्र अपनी भाषा में अध्ययन कर सकेंगे तथा उनके लिए कई नए अवसरों के द्वार भी खुलेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मां और मातृभाषा मिलकर जीवन को मजबूती प्रदान करते हैं तथा कोई भी इंसान अपनी मां एवं मातृभाषा को न छोड़ सकता है और न ही इनके बिना उन्नति कर सकता है। मैं तो मातृभाषा के लिए यही कहूंगा कि जैसे हमारे जीवन को हमारी मां गढ़ती है, वैसे ही मातृभाषा भी हमारे जीवन को गढ़ती है। मां और मातृभाषा दोनों मिलकर जीवन के आधार को मजबूत बनाते हैं, चिरंजीव बनाते हैं। जैसे हम अपनी मां को नहीं छोड़ सकते, वैसे ही अपनी मातृभाषा को भी नहीं छोड़ सकते। मुझे बरसों पहले अमेरिका में एक बार एक तेलुगू परिवार में जाना हुआ और मुझे एक बहुत खुशी का दृश्य वहां देखने को मिला। उन्होंने मुझे बताया कि हम लोगों ने परिवार में नियम बनाया है कि कितना ही काम क्यों न हो, लेकिन अगर हम शहर के बाहर नहीं हैं तो परिवार के सभी सदस्य भोजन की मेज पर बैठकर तेलुगू भाषा बोलेंगे। जो बच्चे वहां पैदा हुए थे, उनके लिए भी ये नियम था। अपनी मातृभाषा के प्रति ये प्रेम देखकर इस परिवार से मैं बहुत प्रभावित हुआ था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी कुछ लोग ऐसे द्वन्द्व में हैं जिसके कारण उन्हें अपनी भाषा, अपने पहनावे, अपने खान-पान को लेकर संकोच होता है, जबकि विश्व में कहीं और ऐसा नहीं है। मातृभाषा को गर्व के साथ बोला जाना चाहिए और हमारा देश तो भाषाओं के मामले में इतना समृद्ध है कि उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। हमारी भाषाओं की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक सैंकड़ों भाषाएं, हजारों बोलियां एक दूसरे से अलग लेकिन एक दूसरे में रची-बसी हैं। हमारी भाषा अनेक, लेकिन भाव एक है।

भाषा, केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं, अपितु भाषा समाज की संस्कृति और विरासत को भी सहेजने का काम करती है। हमारे यहां भाषा की अपनी खूबियां हैं, मातृभाषा का अपना विज्ञान है। इस विज्ञान को समझते हुए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर बल दिया गया है।

सरकार की नीति सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और भारतीय भाषाओं को जीवंत बनाए रखने के प्रयासों पर विशेष बल देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत सरकार ने यह प्रावधान किया है कि जहां तक संभव हो, कम से कम कक्षा पांच तक और अधिमानतः कक्षा आत्ह तक शिक्षा का माध्यम गृह भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा में होगा। नीति इस बात पर बल देती है कि शिक्षण गृह भाषा/स्थानीय भाषा में हो और भारतीय भाषाओं को विद्यालयीय और उच्च शिक्षा के साथ एकीकृत किया जाए, ताकि छात्रों के पास किसी भी भारतीय भाषा में अध्ययन करने का विकल्प हो। केंद्रीय हिंदी निदेशालय एवं केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए कार्य करते हैं, जबकि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग सभी भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दावली विकसित करने के लिए कार्य करता है।

भारतीय भाषा संवर्धन अनुदान योजना के अंतर्गत, भारत सरकार केन्द्रीय हिंदी संस्थान, महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद और राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद को क्रमशः हिंदी, वेद, शास्त्रीय तमिल, सिंधी एवं उर्दू के संवर्धन के लिए अनुदान प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार तीन केंद्रीय विश्वविद्यालयों, अर्थात् केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर

शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति के माध्यम से संस्कृत भाषा को बढ़ावा दे रही है। इन विश्वविद्यालयों को संस्कृत भाषा में शिक्षण और अनुसंधान के लिए धनराशि प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से छात्रों को डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिया है। इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने स्थान के अनुसार किसी भी भाषा का आधिकारिक भाषा के चयन कर सकती है। केंद्र सरकार ने अपने कार्यों के लिए हिन्दी तथा रोमन भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिया है। इसके अतिरिक्त राज्यों ने स्थानीय भाषा के अनुसार भी आधिकारिक भाषाओं का चयन किया है। इन 22 आधिकारिक भाषाओं में असमी, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संतली, सिंधी, तमिल, तेलुगू, बोड़ो, डोगरी, बंगाली एवं गुजराती सम्मिलित है।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अनुसार- "चाहे वह तमिलनाडु हो या कर्नाटक या आंध्र या केरल, इन क्षेत्रों की भाषाएं समृद्ध भाषाएं हैं। इनका साहित्य प्राचीन है, हिंदी अपेक्षाकृत नई भाषा है, हिंदी खड़ी बोली का रूप है या मैं कहूं यह खड़ी बोली है तो कोई आपत्ति नही होनी चाहिए। इससे पहले अनेक बोलियां थीं, वे भी संपन्न थीं, वे समृद्ध थीं और आज भी हैं। उनके प्रयोग की फिर से प्रवृत्ति बढ़ रही है, यह एक अच्छी प्रवृत्ति है.लेकिन दक्षिण में मैं जाता हूं, और अब दक्षिण में हिंदी बोलना कठिनाई का कारण नहीं है। थोड़ा सा यह ध्यान रखना पड़ता है कि जो पहला वाक्य है, वह उनकी मातृभाषा में होना चाहिए। वह तेलुगू में होना चाहिए, तमिल में होना चाहिए। 'सोदर-सोदरी मनुरा'- यह कहने के बाद आप हिंदी पर पहुंच जाएं, तो कोई आपत्ति नहीं करेगा, कोई बाधा पैदा नहीं करेगा. तमिलनाडु में 'वणक्कम'- यह मानो सारे दरवाजे खोल देता है। हृदय के भी दरवाजे खोल देता है। भाषा में इतनी शक्ति है, एक शब्द में इतना प्रभाव है। हमारी भाषाएं विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का माध्यम बनें, अनुसंधान की भाषा बनें, और फिर पराई भाषा यह दायित्व पूरा नहीं कर सकती। उसके लिए अपनेपन की भाषा चाहिए। अन्य भाषाओं का भी हम अध्ययन करें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन अनुसंधान के लिए, खोज के लिए और वर्तमान को अतीत से जोड़ने के लिए और वर्तमान को भविष्य से संबंधित करने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी भाषाओं का विकास करें। उन्हें आधुनिक ज्ञान विज्ञान का माध्यम बनाएं और उनके द्वारा आम आदमी तक पहुंचने की आवश्यकता को भी पूरा करें और उनके द्वारा राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता, इनको भी बलशाली रूप में प्रस्तुत करने का अभियान करें।"

लेखक - लखनऊ विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष हैं.



महिला सशक्तिकरण की राह में राजनीति का रोड़ा !



भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी हमेशा से एक ज्वलंत और प्रतीक्षित मुद्दा रही है। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' यानी महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का कानून, जो दशकों से अधर में लटका है, एक बार फिर भारतीय राजनीति के केंद्र में है। इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच छिड़ी जुबानी जंग ने देश की आधी आबादी के अधिकारों पर एक नई बहस छेड़ दी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2023) का मुख्य उद्देश्य लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करना है। यह महज एक कानून नहीं, बल्कि उस सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम है जिसे पहली बार 1996 में एचडी देवेगौड़ा सरकार के दौरान पेश किया गया था। हालांकि, हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों ने इसके क्रियान्वयन पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। 17 अप्रैल 2026 को संसद में पेश किया गया 131वां संविधान संशोधन विधेयक, जो इस आरक्षण को 2029 के चुनावों से ही लागू करने के लिए परिसीमन (Delimitation) की प्रक्रिया को तेज करना चाहता था, संसद में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत न मिल पाने के कारण गिर गया। बीजेपी और एनडीए (NDA) का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं का तर्क है कि विपक्ष ने इस महत्वपूर्ण संशोधन का विरोध करके अपनी महिला विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है।

सरकार का कहना है कि वे महिलाओं को उनका हक देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन विपक्षी दल जनगणना और परिसीमन के तकनीकी बहाने बनाकर इसे रोकना चाहते हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस और क्षेत्रीय दल (TMC, सपा) केवल परिवारवादी राजनीति को बढ़ावा देते हैं और उन्हें आम महिलाओं के नेतृत्व से डर लगता है।

विपक्ष की घेराबंदी

दूसरी ओर, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (TMC) और समाजवादी पार्टी (SP) जैसे दलों ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनके विरोध के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

ओबीसी (OBC) कोटा की मांग: विपक्ष का तर्क है कि बिना 'कोटा के भीतर कोटा' (अर्थात ओबीसी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण) के यह बिल अधूरा है और इससे पिछड़ी जातियों की महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा।

क्रियान्वयन में देरी: विपक्ष इसे बीजेपी का चुनावी स्टंट करार दे रहा है। उनका कहना है कि सरकार ने बिल तो पास कर दिया, लेकिन इसे लागू करने की शर्त 'जनगणना' और 'परिसीमन' से जोड़ दी है, जिससे यह अगले कई सालों तक हकीकत नहीं बन पाएगा।

दक्षिण बनाम उत्तर का विवाद: विपक्षी दलों का यह भी कहना है कि जनगणना आधारित परिसीमन से उन राज्यों (विशेषकर दक्षिण भारतीय राज्यों) को नुकसान होगा जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया है।

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर चल रहा यह घमासान केवल नीतिगत मतभेद नहीं, बल्कि वोट बैंक की गहरी राजनीति का हिस्सा भी है। जहां एक तरफ महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने का दावा है, वहीं दूसरी तरफ जातियों और क्षेत्रीय संतुलन की जटिलताएं हैं।

अंततः, महिला आरक्षण केवल संसद में सीटों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज के हर वर्ग की महिलाओं को नीति-निर्धारण की मेज पर जगह मिले। क्या राजनीति की इस खींचतान में महिलाओं का हक फिर से देरी की भेंट चढ़ जाएगा, या 2029 में भारतीय लोकतंत्र की तस्वीर सचमुच बदली हुई दिखेगी? यह आने वाला समय ही बताएगा।

आंखों में रोशनी, जिंदगी में उम्मीद



योगेश अग्निहोत्री

जब नेत्र चिकित्सा केवल इलाज नहीं, बल्कि मरीज के भरोसे और बेहतर जीवन की नई शुरुआत बन जाए

किसी इंसान की जिंदगी में आंखों की अहमियत को शब्दों में बांधना आसान नहीं है। आंखें केवल दुनिया को देखने का माध्यम नहीं, बल्कि अपनों के चेहरे पहचानने, अपने कदमों पर चलने और आत्मनिर्भर जीवन जीने की ताकत भी हैं। ऐसे में जब मोतियाबिंद या अन्य नेत्र समस्याओं के कारण किसी की दुनिया धुंधली होने लगती है, तो सही इलाज उसके लिए सिर्फ चिकित्सा नहीं, बल्कि जिंदगी में लौटती उम्मीद बन जाता है। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही हैं डॉ. पल्लवी सिंह चौहान। चिकित्सा विशेषज्ञता के साथ मरीजों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण उनकी कार्यशैली की महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में सामने आता है। डॉ. पल्लवी सिंह चौहान एम.एस. हैं और उन्होंने Comprehensive Ophthalmology Fellowship भी प्राप्त की है। वह अस्पताल के नेत्र चिकित्सा विभाग से जुड़ी हैं और नेत्र रोगों के उपचार एवं मरीजों की देखभाल में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

जब मरीज को केवल डॉक्टर नहीं, भरोसे की जरूरत होती है

नेत्र रोग विशेषज्ञ के सामने पहुंचने वाला हर मरीज केवल अपनी बीमारी लेकर नहीं आता। कई बार वह आंखों की रोशनी कम होने का डर, भविष्य की चिंता और परिवार पर निर्भर हो जाने की आशंका भी अपने साथ लेकर आता है। ऐसे समय में डॉक्टर की भूमिका केवल बीमारी की पहचान और उपचार तक सीमित नहीं रहती। मरीज को यह भरोसा दिलाना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसकी समस्या को समझा जा रहा है और उसके उपचार के लिए सही दिशा मौजूद है। डॉ. पल्लवी सिंह चौहान के पेशेवर सफर का यही मानवीय पक्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण नजर आता है-जहां चिकित्सा विज्ञान के साथ मरीज की मानसिक स्थिति और उसके भरोसे को भी महत्व दिया जाता है।

एक ऑपरेशन... और फिर साफ नजर आने लगती है दुनिया

मोतियाबिंद जैसी समस्या उम्र के साथ अनेक लोगों की दृष्टि को प्रभावित करती है। धीरे-धीरे धुंधलाती दुनिया व्यक्ति की दिनचर्या और आत्मनिर्भरता दोनों पर असर डाल सकती है। लेकिन सफल उपचार के बाद वह क्षण बेहद भावनात्मक हो सकता है, जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति फिर से अपने परिवार के चेहरों को साफ देख पाता है।

किसी मां के लिए अपने बच्चों की मुस्कान, किसी पिता के लिए परिवार के चेहरों की पहचान, और किसी दादा-दादी के लिए अपने





पोते-पोतियों को स्पष्ट रूप से देख पाना, ये पल केवल दृष्टि बेहतर होने की कहानी नहीं हैं। ये उस आत्मविश्वास की वापसी हैं, जो बीमारी के कारण कहीं पीछे छूट गया था।

15,000 सफल सर्जरी का अनुभव और संस्थागत विश्वास

VAGA Hospital अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 15,000 सफल सर्जरी का उल्लेख करता है। यह आंकड़ा संस्थान के चिकित्सा अनुभव और बड़ी संख्या में मरीजों तक पहुंची स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर प्रस्तुत करता है। ऐसे संस्थागत वातावरण में कार्य करते हुए डॉ. पल्लवी सिंह चौहान (निदेशक) नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के माध्यम से मरीजों को जांच, परामर्श और उपचार की दिशा प्रदान कर रही हैं। चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक और विशेषज्ञता की भूमिका लगातार बढ़ रही है, लेकिन किसी मरीज के लिए डॉक्टर का सहज व्यवहार और उसकी समस्या को ध्यान से सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यही संतुलन स्वास्थ्य सेवा को केवल इलाज से आगे ले जाकर भरोसे का रिश्ता बनाता है।

निःशुल्क नेत्र शिविर: जहां इलाज से पहले पहुंचती है उम्मीद

नेत्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जरूरतमंद लोगों तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने में स्वास्थ्य शिविरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति आंखों की समस्या लेकर निःशुल्क जांच शिविर में पहुंचता है, तो उसके लिए यह केवल जांच कराने का अवसर नहीं होता। उसे विशेषज्ञ सलाह मिलती है, अपनी समस्या को समझने का अवसर मिलता है और जरूरत के अनुसार आगे के उपचार की दिशा भी तय होती है। कई ऐसे लोग होते हैं जो आर्थिक कारणों, जानकारी के अभाव या लापरवाही के चलते लंबे समय तक आंखों की समस्या को नजरअंदाज करते रहते हैं। ऐसे में शिविरों के माध्यम से उन तक पहुंचना नेत्र स्वास्थ्य जागरूकता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

सेवा का वह पक्ष, जहां मरीज सबसे पहले है

चिकित्सा केवल डिग्री और तकनीक का क्षेत्र नहीं है। यह संवेदना, धैर्य और विश्वास का भी पेशा है। किसी जरूरतमंद मरीज को समय देना, उसकी परेशानी को सुनना और उसे सही उपचार की दिशा बताना-यही वे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो डॉक्टर और मरीज के रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। डॉ. पल्लवी सिंह चौहान की प्रोफाइल भी इसी विचार के इर्द-गिर्द आकार लेती है- विशेषज्ञता के साथ संवेदनशीलता और उपचार के साथ विश्वास।

रोशनी लौटती है, तो जिंदगी भी बदलती है

आंखों का सफल इलाज कई बार किसी व्यक्ति के जीवन में एक नया अध्याय खोल देता है। धुंधलेपन से साफ दृष्टि तक का सफर केवल आंखों का बदलाव नहीं होता, बल्कि उसके आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और जीवन की गुणवत्ता में भी बदलाव ला सकता है। शायद यही कारण है कि नेत्र चिकित्सा में हर सफल उपचार के पीछे केवल एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि किसी की उम्मीद, किसी परिवार की खुशी और जिंदगी को फिर से साफ नजरों से देखने की इच्छा भी होती है।

डॉ. पल्लवी सिंह चौहान की चिकित्सा यात्रा को इसी मानवीय दृष्टि से देखा जा सकता है-जहां उद्देश्य केवल आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि मरीज के जीवन में भरोसे और उम्मीद का उजाला बनाए रखना भी है। "क्योंकि जब आंखों में रोशनी लौटती है, तो सिर्फ दुनिया साफ दिखाई नहीं देती-जिंदगी भी नई उम्मीदों के साथ मुस्कुराने लगती है।"

हल्दी में सीसा: स्वाद, सेहत और सुरक्षा का सवाल

सीसा एक अत्यंत विषैला भारी धातु है, जिसका शरीर में कोई सुरक्षित स्तर नहीं माना जाता। विशेष रूप से बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए इसका प्रभाव अत्यंत हानिकारक हो सकता है। सीसा के लगातार संपर्क से बच्चों की बौद्धिक क्षमता (IQ) में कमी, सीखने में कठिनाई, व्यवहार संबंधी समस्याएँ, एनीमिया और मस्तिष्क के विकास पर स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। वहीं वयस्कों में यह उच्च रक्तचाप, गुर्दे की बीमारी, हृदय संबंधी समस्याएँ तथा प्रजनन स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बाजार में बिकने वाली हल्दी में अत्यधिक मात्रा में सीसा पाए जाने की कई वैज्ञानिक रिपोर्टें सामने आई हैं। कई मामलों में इसका कारण लेड क्रोमेट (Lead Chromate) नामक पीले रंग के रसायन की मिलावट पाया गया, जिसे हल्दी का रंग अधिक चमकीला दिखाने और उसकी बाजार कीमत बढ़ाने के लिए अवैध रूप से मिलाया जाता है। यह खाद्य मिलावट का एक गंभीर उदाहरण है, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इसी संदर्भ में टॉक्सिक्स लिंक द्वारा किए गए एक अध्ययन ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास किया—क्या हल्दी में सीसा खेत में ही आता है या बाद की प्रक्रिया में मिलाया जाता है? अध्ययन के अंतर्गत छह राज्यों से किसानों के खेतों से सीधे 13 कच्ची हल्दी के नमूने एकत्र कर NABL-मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में उनकी जाँच कराई गई। अध्ययन के परिणाम उत्साहजनक रहे। सभी नमूनों में सीसा की मात्रा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्धारित 10 mg/kg की सीमा से काफी कम पाई गई। अधिकांश नमूनों में सीसा का स्तर 0.5 mg/kg से भी कम था तथा केवल एक नमूने में 1.87 mg/kg दर्ज किया गया। इससे संकेत मिलता है कि खेतों में उगाई गई कच्ची हल्दी सामान्यतः सुरक्षित है और मिट्टी या सिंचाई जल से होने वाला प्रदूषण इस अध्ययन में प्रमुख कारण के रूप में सामने नहीं आया। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि यदि बाजार में बिकने वाली हल्दी में अधिक मात्रा में सीसा पाया जाता है, तो उसका स्रोत संभवतः कटाई के बाद की प्रक्रियाएँ-जैसे प्रसंस्करण, पॉलिशिंग, पैकेजिंग या जानबूझकर की गई मिलावट-हो सकती हैं। इसलिए आवश्यकता है कि केवल खेतों पर नहीं, बल्कि पूरी आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी की जाए। यदि यह निष्कर्ष व्यापक स्तर पर और अधिक अध्ययनों से पुष्ट होते हैं, तो खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के लिए यह एक महत्वपूर्ण संदेश होगा। निगरानी का केंद्र केवल खेती तक सीमित न रहकर पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर होना चाहिए। प्रसंस्करण इकाइयों का नियमित निरीक्षण, बाजार में उपलब्ध हल्दी और अन्य मसालों का समय-समय पर परीक्षण, आधुनिक ट्रेसबिलिटी प्रणाली का विकास तथा मिलावट करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आवश्यक है। साथ ही किसानों, व्यापारियों, प्रसंस्करण इकाइयों और निर्यातकों को भी इस समस्या के स्वास्थ्य और आर्थिक दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना होगा। उपभोक्ता भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमेशा विश्वसनीय और प्रमाणित स्रोतों से हल्दी खरीदें, अत्यधिक चमकीले रंग वाली संदिग्ध या असामान्य रूप से सस्ती हल्दी से बचें तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी जागरूकता बढ़ाएँ। सुरक्षित भोजन केवल सरकारी नियमों से नहीं, बल्कि जागरूक उपभोक्ताओं और जिम्मेदार उद्योग से भी सुनिश्चित होता है। भारत विश्व के सबसे बड़े हल्दी उत्पादक और निर्यातक देशों में से एक है। इसलिए हल्दी की गुणवत्ता केवल स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं, बल्कि किसानों की आजीविका, उपभोक्ताओं के विश्वास और भारतीय मसालों की वैश्विक प्रतिष्ठा से भी जुड़ी हुई है। विज्ञान, प्रभावी नियमन और सामाजिक जागरूकता के संयुक्त प्रयासों से ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि हमारी थाली तक पहुँचने वाली हल्दी वास्तव में स्वास्थ्य का प्रतीक बनी रहे, न कि किसी अदृश्य विषैले खतरे का माध्यम।



मातृशक्ति का सम्मान



60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की
उत्तर प्रदेश की महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा
की सुविधा

'लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा' योजना





योजना साकार-संवेदनशील सरकार

- लोक कल्याण संकल्प पत्र का वादा पूरा
- 60 वर्ष+ आयु की महिलाओं को आजीवन निःशुल्क यात्रा की सुविधा
- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा
- पात्र महिलाओं को निगम द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे विशेष स्मार्ट कार्ड
- आधार कार्ड दिखाकर भी पात्र महिलाएं उठा सकेंगी लाभ
- योजना पर ₹22 करोड़+ मासिक व्यय भार अनुमानित
- प्रतिदिन 88,000+ महिला यात्रियों को लाभ मिलने का अनुमान

मातृशक्ति लाभ उठाएं-मनचाही यात्रा पर जाएं

विकास की गति अपार
डबल इंजन सरकार

परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076



मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों,

भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की अर्धरात्रि में मथुरा के कारागार में जब नंदलाला का प्राकट्य हुआ, तब असत्य और अन्याय के अंधकार के बीच सत्य और धर्म का प्रकाश प्रस्फुटित हुआ। **भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाएं मन को आनंदित करने वाली कथाएं मात्र नहीं, बल्कि उनमें गहन आध्यात्मिक संदेश निहित हैं।** माखन चोरी में सहजता और निश्छलता, गोप-गोपियों के साथ उनकी आत्मीयता में प्रेम और समरसता तथा कालिय नाग के दमन में अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश मिलता है। **इस पावन अवसर पर आप सभी को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (५ सितम्बर, 2026) की हृदय से शुभकामनाएं।**

भगवान श्रीकृष्ण का जीवन हमें बताता है कि समाज की शक्ति सामूहिक सहकारिता में निहित है। **गोवर्धन पर्वत धारण कर उन्होंने प्रकृति, पशुधन और कृषि-आधारित जीवन के संरक्षण तथा सामूहिक एकजुटता का संदेश दिया।** वृंदावन से लेकर बरसाना की राधारानी और नंदगांव की प्रेममयी स्मृतियों तक, ब्रज की धरती आज भी उस दिव्य चेतना को अपने कण-कण में संजोए हुए है।

श्रीकृष्ण कुलीनता के नहीं, समरसता के प्रतीक हैं। वे समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ खड़े रहे। वे द्वारकाधीश हैं, तो सुदामा के आत्मीय मित्र भी। सांदीपनि ऋषि के आश्रम में उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और सुदामा के साथ उनकी मित्रता ने बताया कि सच्चे संबंध पद, प्रतिष्ठा और संपन्नता से नहीं, आत्मीयता से बनते हैं। यही समरसता, समानता और आत्मीयता आज के समाज की आवश्यकता है।

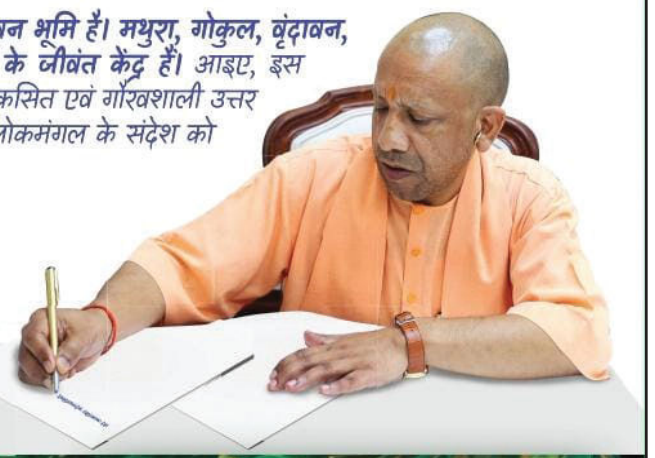
योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण का जीवन हमें लोककल्याणकारी शासन की मूल भावना की प्रेरणा भी देता है। **अन्याय का प्रतिकार, धर्म की रक्षा, निर्बल का संरक्षण और लोकमंगल उनके जीवन-दर्शन के प्रमुख आधार रहे। आज इसी भाव के साथ हमारी सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है।** गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश, प्रतिभासंपन्न निपुण युवाओं को काम, अन्नदाताओं को सहारा एवं बेटियों को बेटों के समान आगे बढ़ने का अवसर, लोककल्याण की इसी भावना को धरातल पर उतारने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है।

गीता में योगेश्वर श्रीकृष्ण ने कर्म, ज्ञान और कर्तव्य का जो मार्ग दिखाया, वह केवल किसी एक युग के लिए नहीं है। दैनंदिन जीवन की प्रत्येक चुनौती में इससे बड़ा मार्गदर्शन शायद ही कुछ और हो। निष्काम कर्म, सत्य के प्रति निष्ठा और लोकमंगल की भावना हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग बनाती है।

उत्तर प्रदेश की धरती श्रीकृष्ण की लीलाओं और संदेशों की पावन भूमि है। मथुरा, गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना और नंदगांव हमारी सनातन सांस्कृतिक चेतना के जीवंत केंद्र हैं। आइए, इस जन्माष्टमी पर अपनी विरासत के संरक्षण, सामाजिक समरसता और विकसित एवं गौरवशाली उत्तर प्रदेश के निर्माण का संकल्प लें तथा श्रीकृष्ण के सत्य, धर्म, कर्म और लोकमंगल के संदेश को अपने जीवन में उतारें।

आपका

योगी आदित्यनाथ



जय कन्हैयालाल की

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP